▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

मार्गशीर्ष–पौष 2080, जनवरी 2024

घटता हुआ दोहरा घाटा

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

सचित्र झलक

बैठकें

पलक्कड़, केरल

तेलंगाना

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI

Patrika

स्वदेशी

पत्रिका

पढ़ें और

पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

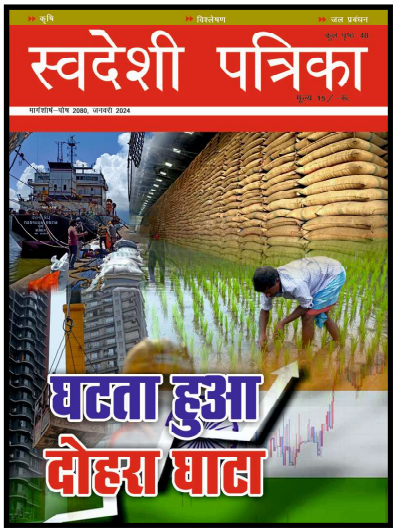

वर्ष–32, अंक–1
मार्गशीर्ष–पौष 2080 जनवरी 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–08

घटता हुआ दोहरा घाटा

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 बहस
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पक्षपात पूर्ण
..... के.के. श्रीवास्तव

10 आजकल
हर क्षेत्र में बढ़ रही है स्वदेशी की शक्ति
..... अनिल तिवारी

12 विश्लेषण
आर्थिक केंद्र भी है राम मंदिर
..... स्वदेशी संवाद

14 मुद्दा
क्यों अमेरिका जाते हैं, सबसे अधिक अवैध अप्रवासी
..... विक्रम उपाध्याय

16 विमर्श
मजबूत अर्थव्यवस्था में कमजोर होती गरीब की थाली
..... स्वदेशी संवाद

18 विचार
भारत के लिए पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू काश्मीर का महत्वः वापसी क्यों आवश्यक?
..... विनोद जौहरी

20–21
स्वदेशी–विदेशी सामान की सूची

22 जल प्रबंधन
जल संतुलन के लिए जरूरी है तालाबों का पुनरुद्धार
..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

24 पर्यटन
उत्तर प्रदेश में बढ़ता धार्मिक पर्यटन एवं उत्पादों का उपभोग
..... प्रहलाद सबनार्नी

26 अध्यात्म
भगवान श्री राम का पर्यावरण प्रेम
..... डॉ. राजीव कुमार

29 स्वदेशी गतिविधियां
अखिल भारतीय वृहद बैठक, कन्याकुमारी (23–25 दिसंबर 2023)

पाठकनामा

राम का दर्शन हो, उनके नाम पर प्रदर्शन नहीं

श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भावी पावन पल करीब 500 सालों के दीर्घ संघर्ष यात्रा का परिणामफल है। इस आंदोलन में मानव निर्मित संकटों के सेतु पार कर असंख्य बलिदान देकर एवं उच्चतर न्यायिक निर्णय के बाद नैसर्गिक आस्था के धवल ध्वज को फहराने का स्वर्णिम समय लौटा है। देव दर्शन के लिए आमंत्रण पत्र अनिवार्य नहीं होता इसलिए अपने राम को याद कीजिए और उनके धाम पहुंचिए क्योंकि यह राम का घर है और यहां सब का स्वागत है।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को भी इसे 2024 में होने जा रहे आम चुनाव के चश्मे से देखना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल का नेता ऐसा करेगा तो अपने हाथों अपने राजनीतिक दल की छवि खराब करने का ही काम करेगा क्योंकि जनता सब जानती है। लंबे समय के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी इससे हमारा देश एक बार फिर उसी तरह राममय हो जाएगा जिस तरह जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। भगवान राम सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म के लिए ही आदर्श नहीं बल्कि हर धर्म के लिए हैं। राम जी का भव्य मंदिर जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो देश–विदेश के लोग यहां आकर प्रभु श्रीराम के नाम की महिमा का गुणगान करेंगे। इससे एक तो अयोध्या के आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दूसरा विदेशियों के यहां आने से विदेशी मुद्रा हमारे देश आएगी। इससे सरकारी खजाने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम सभी के लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। इस काम से सबका भला होना है। हम सभी को भगवान राम के आदर्शों पर चलना होगा। उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी होगी। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। वर्तमान के झंझावातों से निकलकर सुखद भविष्य बनाने का यही रास्ता भी है।

सिया राम मय सब जग जानी। करहि प्रणाम जोरि–जुग पानी।।

डॉ. पराक्रम सिंह, *ग्राम–धुंधुरी, जिला–आजमगढ़, उत्तर प्रदेश*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और उन्नति में बाधा न बने।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

मैं पूरे उद्योग से आग्रह करूंगा कि वे आपके अंतिम उत्पाद के भीतर घरेलू खरीद और घरेलू मूल्य को उच्चतम संभव स्तर तक समर्थन दें।

पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत

मुझे उम्मीद है कि ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) वास्तव में आने वाले वर्षों में एक मजबूत पर्यटन में तब्दील हो जाएगा और पर्यटन रोजगार का एक शक्तिशाली चालक है... ओडीओपी, पर्यटन का एक और अधिक शक्तिशाली चालक बन सकता है, है और बनना भी चाहिए।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत

आत्मनिर्भर भारत सफल रहा, क्योंकि भारत आरसीईपी से बाहर रहा।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

अमीरों का क्लब है वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम

जनवरी 15 से 19 के बीच दुनिया के एक महत्वपूर्ण मंच, वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, का सम्मेलन डावोस (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न हुआ। वर्ष 1971 में आस्तित्व में आया वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम, पिछले लगभग 53 साल से वैश्विक आर्थिक संरचना पर चर्चा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के नाते उभरा है। व्यापार, भू–राजनीति, सुरक्षा, सहकार, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण और प्र.ति समेत अनेकानेक मुद्दों पर इस मंच पर चर्चा होती रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी हस्तियों ने डावोस के इस सम्मेलेन में भाग लिया। 60 देशों के शासनाध्यक्षों के अलावा बड़ी कई संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजनेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां के प्रमुख, और अनेकानेक आर्थिक जगत के प्रमुख महानुभाव इस सम्मेलन में आयोजित बैठकों और गोष्ठियों में दिखे। 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पोषित यह मंच, अपने सम्मेलनों में भाग लेने वालों से मोटी रकम फीस के रूप में लेता है। यानि किसी भी तरह से यह सर्वसमावेशी मंच तो नहीं कहा जा सकता। समाज में कम भाग्यशाली लोगों की ओर से बोलने वालों में से शायद कोई यहां नहीं पहुंच पाता। यह मंच दुनिया की उन विशालकाय कंपनियों की दुनिया का ही मंच कहा जा सकता है, जिनके पैसे से इसका काम चलता है, क्योंकि इसमें दुनिया के सामान्य जन के हित साधने जैसी कोई बात नहीं होती। यदि वर्ष 2024 के ही डावोस में आयोजित वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम की बात करें तो देखते हैं कि 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका सामान्यजन से कोई खास सरोकार दिखाई नहीं देता। वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम के इस मंच पर जिन 60 शासनाध्यक्षों ने भाग लिया वे सभी वैश्विक भू–राजनीति में उथल–पुथल देशों के बीच बढ़ती वैमनस्यता और युद्ध की स्थिति से चिंता व्यक्त करते हुए देखें गए। चाहे उनकी चिंता वाजिब है, लेकिन आर्थिकी की चर्चा करते समय उनका ध्यान मुल्कों के बीच असमानताओं और दुनिया में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी की तरफ नहीं था। एक विषय पर जिसमें पूरे दुनिया का सरोकार है यानि पर्यावरण और मौसम परिवर्तन, उस पर बात तो हुई, लेकिन समाधान के लिए वैश्विक नेताओं में कोई विशेष इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दी।

वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम या अन्य अन्य मंचों पर पर्यावरण की समस्या पर चाहे चर्चा करती होंगी, लेकिन वे अभी भी अपने पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी को भी बिना भारी शुल्क पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए साझा करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दोहरे चरित्र की ओर इंगित करती है। वे सभी महानुभाव जो डावोस की बैठक में भाग लेने आए, उन्होंने दुनिया में बिगड़ते पर्यावरण और बदलते मौसम के कारण तबाही की आशंकाओं पर चर्चा तो की, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने–अपने निजी विमान से वहां आए। उससे कार्बन का कितना उत्सर्जन हुआ और पर्यावरण का कितना ह्रास हुआ, उस ओर वे उदासीन दिखे। ऊंचे शुल्क के कारण इस सम्मेलन में हाशिये पर खड़े समुदायों, पिछड़े समाजों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सामान्य लोगों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता। शासनाध्यक्षों और सरकारों में बड़े मंत्रियों और बड़ी कंपनियों के चहेते चुनिंदा बुद्धिजीवियों की उपस्थिति इन कंपनियों के एजेंडे को वैधता प्रदान करती है। जाहिर है चाहे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मानवता और विश्व कल्याण की कितनी भी बातें करें, इनका इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान व्यवहार दानवों को भी लज्जित करने वाला था। फाइजर नामक कंपनी ने तो अप्रभावी वैक्सीन ही जानबूझ कर दुनिया भर में बेच दी। कंपनी को भली भाँति मालूम था कि उनकी वैक्सीन प्रभावी नहीं, उसके बावजूद वो अमरीकी सरकार के माध्यम से भारत सरकार भी दबाव बना रही थी। यही नहीं अमरीकी दबाव में भारत की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर इसकी वैक्सीन खरीदने हेतु दबाव बना रहीं थी। पिछले वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम (2023) में जब पत्रकारों द्वारा फाइजर कंपनी के प्रमुख से इस बाबत जवाब माँगा गया तो वो कुछ बोलने के लिये तैयार नहीं हुए। यह बात छुपी हुई नहीं है कि 'गैट' समझौतों में अधिकांश समझौते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हुए, ट्रिप्स समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में न केवल दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों समेत सभी प्रकार के उत्पादों पर पेटेंट की अवधि बढ़ाई गई, प्रक्रिया पेटेंट से उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था भी लागू की गई, जिससे दुनिया के सभी देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा बाधित हुई। जब भारत की कैडिला कंपनी से दक्षिण अफ्रीका द्वारा दवाई खरीदने का कंपनियों ने विरोध किया और इसके कारण उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ा तो डब्ल्यूटीओ में मान्य किया गया कि महामारी और अपातकालीन परिस्थितियों में पेटेंट अप्रभावी रहेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि सदी की सबसे भयंकर महामारी के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पेटेंट को अधिकारों को नहीं छोड़ा।

समझा जा सकता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसमें केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही दबदबा हो और जिसमें विश्व के सामान्य प्रतिनिधियों की कोई प्रभावी भूमिका न हो, उससे दुनिया के किसी भी प्रकार के भले की कल्पना नहीं की जा सकती। समझना होगा कि वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम जिसकी विश्व में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है और जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनका धर्म ही लाभ और केवल लाभ कमाना है और जो मानवता के प्रति इतनी अधिक असंवेदनशील है, का ही एक मंच है, उनसे क्या अपेक्षा हो सकती है। 19 जनवरी, 2024 को अमेरिकी प्रतिनिधि स्कॉट पेरी (पीए–10) ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर 'डिफंड डावोस एक्ट' पेश किया, और कहा, *"अमेरिकी करदाताओं को द्वीपीय, वैश्विक अभिजात्य वर्ग के लिए वार्षिक स्की यात्राओं के लिए धन देने के लिए मजबूर करना बेतुका है – निंदनीय तो छोड़ ही दें... विश्व आर्थिक मंच अमेरिकी फंडिंग के एक प्रतिशत के लायक भी नहीं है, और यह सही समय है जब हम दावोस को निधि से वंचित कर रहे हैं।"* इससे पता चलता है कि का अमेरिका में भी कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि यह अभिजात्य वर्ग है और दुनिया के आम आदमी के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

घटता हुआ दोहरा घाटा

राजकोषीय घाटा और चालू खाते पर भुगतान संतुलन में घाटा, दो ऐसे घाटे हैं जो लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान कर रहे थे। अर्थशास्त्र में हम इस परिस्थिति को 'ट्विन डेफिसिट' यानी दोहरा घाटा, कहते हैं। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में दोनों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। हालाँकि, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह बहुत छोटी अवधि है, लेकिन आने वाले महीनों में यह दोहरा घाटा किसी भी बड़े पैमाने पर फिर से बढ़ने का कोई बड़ा कारण नहीं दिखता है। चालू वित्त वर्ष (2023–24) की पहली दो तिमाहियों में चालू खाते पर भुगतान संतुलन में घाटा (सीएडी), घटकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत हो गया है, जबकि अप्रैल से नवंबर 2023 तक पहले आठ महीनों में, राजकोषीय घाटा, पूरे वर्ष के लिए अनुमानित कुल राजकोषीय घाटे का लगभग 50 प्रतिशत दर्ज किया गया है। पूरे वर्ष के लिए अनुमानित कुल राजकोषीय घाटे, यानी 17.86 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इन आठ महीनों के लिए वास्तविक राजकोषीय घाटा केवल 9.06 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि यही प्रक्षेपवक्र चलता रहा, तो पूरे वर्ष (2023–24) के लिए कुल राजकोषीय घाटा 13.5 लाख करोड़ रुपये होगा, जो अनुमानित राजकोषीय घाटे का लगभग 75.4 प्रतिशत होगा। यदि राजकोषीय घाटा मौजूदा अनुमानों से एक लाख करोड़ रुपये अधिक भी हो जाये, तो भी राजकोषीय घाटा अनुमानित आंकड़े का 81 प्रतिशत तक ही होगा।

उल्लेखनीय है कि बजट अनुमानों में वर्ष 2023–24 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कम राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के साथ यह जीडीपी का केवल 4.8 प्रतिशत तक रह सकता है। इसलिए, किसी भी कल्पना से, राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से अधिक नहीं हो सकता, बल्कि यह निश्चित रूप से बजटीय राजकोषीय घाटे से कम हो सकता है।

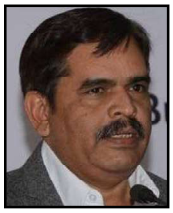

कम दोहरा घाटा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कम घरेलू और विदेशी ऋण और घरेलू मुद्रा के बेहतर मूल्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर ला रहा है। यानी इन आंकड़ों का मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संभावनाएं हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

दोहरा घाटाः राजकोषीय घाटे और सीएडी की जोड़ी

राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का व्यय (राजस्व और पूंजीगत खाते पर) उस वर्ष सरकार द्वारा एकत्र राजस्व से अधिक होता है। हालाँकि, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि दो अलग–अलग अवधारणाएँ हैं, राजकोषीय घाटे का प्राथमिक प्रभाव सार्वजनिक ऋण पर महसूस किया जाता है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में कर्ज में कुल 8.1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा (सीएडी) तब होता है जब किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है। इसका निहितार्थ देश से चालू खाते पर विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह पर है। यह घाटा मुख्य रूप से विदेश से उधार लेकर या विदेशी निवेश के प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों से भरा जाता है। सीएडी का सीधा असर विदेशी मुद्रा की मांग पर पड़ता है, जिससे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है और विदेशी उधार और विदेशी निवेश पर निर्भरता बढ़ती है और आयातित महंगाई भी।

तेजी से बढ़ता राजस्व

हम समझते हैं कि बढ़ती राजस्व प्राप्तियों के कारण राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में

रखा जा सकता है। पिछले आठ माह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, यहां तक घ्धकि बजट अनुमानों से भी अधिक। उदाहरण के लिए, चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में औसत मासिक जीएसटी प्राप्तियां 1.66 लाख करोड़ रुपये रही हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में औसत जीएसटी प्राप्तियों 1.50 लाख करोड़ रुपये से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है और बजट 2023–24 में अनुमानित प्राप्तियों से भी अधिक है। इसी प्रकार पहले आठ महीनों में कॉर्पोरेट टैक्स से 5.14 लाख करोड़ की बड़ी प्राप्तियां देखी गई हैं, जो 2022–23 में इस अवधि में कॉर्पोरेट टैक्स से प्राप्तियों की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत आयकर प्राप्तियां भी 5.67 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो एक साल पहले इस अवधि की प्राप्तियों से 29 प्रतिशत अधिक हैं। कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर की दर कम होने के कारण उत्पाद शुल्क से कम प्राप्तियों के बावजूद, कुल कर प्राप्तियों में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो बजट में अपेक्षित 10.9 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। इन आठ महीनों में सरकारी व्यय भी अनुमान से कम नहीं है, बल्कि बजट में बताई गई राशि से थोड़ा अधिक ही है।

बेहतर सेवा निर्यात

दूसरी ओर, हम सेवाओं के निर्यात में तेजी देख रहे हैं, जिससे भारत को भुगतान शेष में चालू घाटे (सीएडी) को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग एक प्रतिशत तक सीमित करने में मदद मिल रही है। गौरतलब है कि 2022–23 की अंतिम तिमाही में सीएडी, जीडीपी का 3. 8 प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि भारत का सेवाओं का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। वर्ष 2020–21 में सेवाओं का निर्यात मुश्किल से 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही था, जबकि यह 2021–22 में 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवाओं का निर्यात, 2022–23 में 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका था। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सेवा निर्यात 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यदि सेवा निर्यातों में वर्तमान गति बनी रहती है तो वे वर्ष 2023–24 में लगभग 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत से वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि पिछले आठ माह में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें 6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, और चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में यह 279 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही है।

2023–24 के पहले आठ महीनों में माल और सेवाओं का कुल आयात 562. 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, चूंकि माल और सेवाओं का निर्यात 533.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, वित्तीय वर्ष 2023–24 के पहले आठ महीनों के लिए भुगतान शेष में चालू घाटा केवल 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यदि हम पहले आठ महीनों के आधार पर भुगतान शेष में चालू घाटे (सीएडी) का अनुमान लगाएं, तो पूरे वर्ष के लिए कुल सीएडी 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर (3.6 लाख करोड़ रुपये) होगा, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीडीपी 301.75 लाख करोड़ रुपये का 1.19 प्रतिशत ही होगा।

अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर

अनुमानित राजकोषीय घाटा से कम होने से अर्थव्यवस्था के लिए दोहरा लाभ है। पहला, यह कि हम महंगाई को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। हम समझते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति की बदौलत कच्चे तेल की वैश्विक कीमत की तुलना में रूसी तेल की सस्ती खरीद, दूसरी ओर और खाद्य कीमतों पर नियंत्रण के कारण भारत को मुद्रास्फीति दर को अन्य देशों की तुलना में कम रखने में मदद मिली है। अब, राजकोषीय घाटे के अनुमानित से कम होने से सरकार को क़ीमतों को सीमा के भीतर रखने में मदद मिलेगी।

दूसरे, जैसा कि हम समझते हैं, राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से सरकार की उधारी से पाटा जाता है, कम राजकोषीय घाटे का मतलब केंद्र सरकार के ऋण में कम बढ़ोतरी है। विशेष रूप से, बजट 2023–24 के अंत तक केंद्र सरकार का ऋण अनुमान 169.5 लाख करोड़ रुपये दिया गया था, जो कम से कम 3 लाख करोड़ कम हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि यह कम राजकोषीय घाटा अमल में आता है, तो केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत होगा, जबकि 2022–23 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत था।

कम सीएडी अर्थव्यवस्था के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अतीत में, हमारा देश सीएडी के काफी ऊंचे स्तर का अनुभव कर रहा था, जो कभी–कभी सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच जाता था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में यह जीडीपी के 2 प्रतिशत के आसपास रहा है, इसलिए सीएडी का जीडीपी के 1 प्रतिशत के आसपास हो जाना भी कम उपलब्धि नहीं है। उच्च सीएडी विदेशी उधार और विदेशी निवेश पर हमारी निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है और इसका मूल्यह्रास होता है। लेकिन कम सीएडी से रुपया मजबूत होगा, जिसका अर्थ है आयातित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और कई अन्य लाभों के अलावा, विदेशी ऋण पर ब्याज पर कम विदेशी खर्च।

निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कम दोहरा घाटा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कम घरेलू और विदेशी ऋण और घरेलू मुद्रा के बेहतर मूल्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर ला रहा है। यानी इन आंकड़ों का मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संभावनाएं हैं। ❑❑

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पक्षपात पूर्ण

भारत आज सबसे अधिक और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने ऋण पुनर्भुगतान में कभी कोई चूक नहीं की है, लेकिन व्यवहार में भेड़ चाल की अभ्यस्त अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने मनमानी करते हुए पक्षपात पूर्ण तरीके से भारत की स्थिति को कमतर आंकने की हरकत की है। भारत को ऐसे दोषपूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ तेज आवाज उठाने के साथ–साथ ऐसे घटिया व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

मालूम हो कि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु संस्था की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम सहित किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के संबंध में अंतर दृष्टि प्रदान करती है। संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की भूमिका विदेशी ऋण बाजरों में बांड जारी करने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण है। संप्रभु रेटिंग सरकारों की साख को उजागर करने का प्रयास करती है। ऋणदाताओं को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि उधार लेने वाली सरकार अपनी ऋण चुकौती प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगी या नहीं? यदि किसी संप्रभु को दी गई रेटिंग कम है तो डिफॉल्ट का जोखिम अधिक है, क्योंकि सरकार को अधिक लागत पर तब ऋण लेना पड़ेगा। ऐसी रेटिंग्स देश के सभी व्यवसायियों के लिए मायने रखती है ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी देश की सरकार को उस देश के सभी उधारकरताओं में सबसे कम जोखिम भरा माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निडरतापूर्वक की जा रही पक्षपात पूर्ण अनुचित औरदोस्त पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की तत्काल आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ऐसे घटिया व्यवहार के प्रति ज़ीरो टालरेंस होना ही चाहिए।

– के.के. श्रीवास्तव

भारत अन्य विकासशील देशों की तरह पूंजी की कमी से ग्रस्त है। ऐसे में खराब रेटिंग के कारण ऋणदाताओं से उधार लेना और मुश्किल हो जाएगा। एक ओर यह आर्थिक विकास के लिए अपने अन्य संसाधनों का उपयोग करने में विफल रहेगा तो दूसरी ओर उत्पादकता प्रभावित होगी और गरीबी निरंतर बनी रहेगी।

यही कारण है कि तीनों अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिंच द्वारा की गई संप्रभु क्रेडिट रेटिंग न केवल किसी राष्ट्र की उधार लेने की क्षमता बल्कि आर्थिक प्रगति का मार्ग भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत लंबे समय से इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को लेकर चर्चा में रहा है। भारत सरकार की हमेशा शिकायत रही है कि इन एजेंसियों ने भारत की रेटिंग तय करते समय उचित व्यवहार नहीं किया है। एजेंसियों के अनुचित व्यवहार को लेकर भारत ने मोटे तौर पर तीन गंभीर मुद्दे उठाए हैं।

एक–ये रेटिंग एजेंसियां संदिग्ध कार्य प्रणाली अपनाती है जो स्वाभाविक रूप से विकासशील देशों के खिलाफ काम करती प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए रेटिंग एजेंसी फिंच विदेशी स्वामित्व वाले बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक महत्व देती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबदबा है इसके अलावा मूल्यांकन का ऐसा आधार कल्याण और विकास को नजर अंदाज करता है क्योंकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कल्याण को आगे कर वित्तीय समावेशन की पहल प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। (जैसे कि जनधन खाते को लेकर वित्तीय संस्थानों की भूमिका।)

दो–मूल्यांकन परामर्श के लिए विशेषज्ञों का चयन गैर पारदर्शी तरीके से किया जाता

है, जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया और अधिक संदिग्ध हो जाती है।

तीन–ये एजेंसियां विचार किए गए प्रत्येक पैरामीटर के लिए निर्धारित भार निर्दिष्ट नहीं करती हैं। भले ही ऐसे मापदंडों को कुछ संख्यात्मक भार दिए गए हो (उदाहरण के लिए फिंज 4 कारकों पर विचार करता है– संरचनात्मक विशेषताएं, बाहरी वित्त, सार्वजनिक वित्त और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण, नीतियां और संभावनाएं संबंधित सांकेतिक भार के साथ)। किसी भी स्थिति में यह सांकेतिक वजन गणना गलत आधार पर ही आधारित है। इनमें से अधिकांश भार कठिन वास्तविक डाटा पर आधारित नहीं है बल्कि वह व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर अत्यधिक निर्भर हैं।

इन भारों पर पहुंचने के लिए कठिन आर्थिक डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह भार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार, विनिर्माण की गुणवत्ता, इतिहास जैसे मानदंडों पर आधारित हो सकता है। एजेंसियों के मूल्यांकन तरीकों में पारदर्शिता की कमी के कारण प्रभाव की मात्रा तय करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आधे से अधिक क्रेडिट रेटिंग गुणात्मक घटक द्वारा निर्धारित की जाती है। इनमें से अधिकांश घटक वास्तव में संप्रभु की भुगतान करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते हैं।

यदि किसी को वित्तीय मापदंडों पर भारत की वित्तीय ताकत और स्थिरता का आकलन करना है तो भारत निश्चित रूप से इन तीन एजेंसियों द्वारा हाल ही में भारत को दी गई रेटिंग से बेहतर रेटिंग का हकदार है। अंतर–अस्थाई और अंतर–क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर भारत के शानदार आर्थिक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि भारत एक बड़े उन्नयन का प्रबल हकदार है। उदाहरण के लिए मोदी जी ने भारत के

राजकोषीय समेकन पर सीमित प्रगति के नाते चिंता व्यक्त की है। हालांकि भारत का राजकोषीय घाटा लक्षित स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सका है लेकिन इसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा बहुत ही कम दिखाई देता है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026 तक 4.5 प्रतिशत घाटे का लक्ष्य रख रही है जो चालू वर्ष में 5.9 प्रतिशत से थोड़ा कम है। भारत अपना लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखता है क्योंकि हाल के महीना में राजस्व में भारी उछाल आया है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 28 तक देश का ऋण स्तर सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत को पार कर सकता है। लेकिन हमें यहां ठहर कर देखना होगा कि इसी समय अवधि में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के लिए ऋण का स्तर क्रमशः 160 प्रतिशत, 140 प्रतिशत और 200 प्रतिशत आंका गया है। केंद्र और राज्यों को मिलाकर संयुक्त रूप से भारत का सामान्य सरकारी ऋण 88 प्रतिशत से घटकर 81 प्रतिशत तक आ गया है। बांड बाजार के माध्यम से विदेशी निवेश प्रवाह में उत्साहजनक रुझानों के कारण सरकारी उधारी में और भी कमी आने की उम्मीद है। ऐसे में रेटिंग एजेंसियों को विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान के आरामदायक संतुलन सहित वित्तीय मापदंडों को दिए गए भार को काफी हद तक संशोधित करने की जरूरत है।

अतीत में कई मौको परयह निर्णायक रूप से स्थापित हो चुका है की रेटिंग एजेंसियां समय से काफी पीछे रहती हैं और खासकर तनाव के समय में भेड़ चाल का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं।

सुशासन, लोकतंत्र, नागरिकों की आवाज और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कानून का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण यह सभी अपने आप में लक्ष्य हैं लेकिन ऋण चुकाने की क्षमता अंतत देश के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

भारत के लिए सुधार की गुंजाइश है लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी अपनी रेटिंग में अधिक उद्देश्यपूर्ण मात्रात्मक और पारदर्शी होने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना ऐसा किये उनकी विश्वसनीयता हमेशा शक के दायरे में होगी। लेकिन हमें कुछ प्रश्नों का भी समाधान करना होगा। पहला मुद्दा डाटा गुणवत्ता से संबंधित है जिस पर वर्तमान में बहस चल रही है। जनगणना डेटा के साथ–साथ घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण डेटा को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर वैश्विक पूंजी के कुशल आवंटन के लिए निश्चित रूप से रेटिंग का खेल एक समान मैदान पर खेले जाने की आवश्यकता है ताकि निष्पक्ष रेटिंग सुनिश्चित की जा सके। भारत हर तरह की निष्पक्षता का हमेशा पक्षधर रहा है। ❑❑

हर क्षेत्र में बढ़ रही है स्वदेशी की शक्ति

आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पथ पर दौड़ रहे भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का झंडा बुलंद किया है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल भारत अब खुद बना रहा है, वही युद्ध पोत और हल्के लड़ाकू विमान से लेकर घातक ड्रोन तक बनाकर पूरी दुनिया में स्वदेशी का लोहा मनवाया है। अपने स्वदेशी तकनीक के बूते चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया बल्कि अब रक्षा उत्पादों के निर्यात का आंकड़ा 23 गुना बढ़ाते हुए पहले के 686 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022–23 में 16000 करोड़ से ऊपर का करने में सफलता अर्जित की है।

केंद्र की राजग सरकार के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों उपकरणों और तकनीक के बूते आत्मनिर्भर बनने की राह पर दौड़ रहा है। स्वावलंबी भारत अभियान के जरिए स्वदेशी को मिली तरजीह के कारण ही स्वदेशी हथियारों, मिसाइल, हल्के फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम में दुनिया अब दिलचस्पी दिखा रही है। आज भारत पचासी से अधिक देशों को स्वदेशी हथियार और उपकरण, कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत अभियान की बदौलत हथियारों के आयात पर होने वाले खर्च में भी गिरावट आई है। वर्ष 2018–19 में रक्षा क्षेत्र पर खर्च होने वाले कुल लागत में से 46 प्रतिशत हथियारों और सिस्टम पर खर्च हुआ था। दिसंबर 2022 में यह खर्च गिरकर 35.6 प्रतिशत पर आ गया है।

भारत ने चांद पर कदम रख पूरी दुनिया को एक तरह से चौंका दिया है। शुद्ध स्वदेशी उपकरणों से लैस इसरो का चंद्रयान–3 का सफल प्रक्षेपण कर भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसी तरह सूरज को समझने के लिए इसरो ने आदित्य एल–1 का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह देश का पहला अंतरिक्ष अभियान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य एल–1 सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास बिंदु लैंग्रेज पॉइंट वन जिसे एल–1 कहा जाता है, वहां स्थापित होगा। यानी सूर्य की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सूर्य को समझने के लिए यह यान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

स्वदेशी तकनीक और हमारी युवा मेधा के बदौलत भारत हर दिन प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भारत कई और मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा।

–अनिल तिवारी

स्वदेशी की बदौलत भारत अंतरिक्ष की दुनिया में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का अंतरिक्ष बाजार वर्ष 2040 तक 40 से 100 अरब डॉलर के पार होने की उम्मीद है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दुनिया के चार देशों ने छह मसौदे पर इसरो के साथ करार किया है। अंतरराष्ट्रीय मिशन को अंजाम देने से भारत को 14.01 करोड डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 100 अधिक स्टार्टअप चल रहे हैं। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी बढ़कर 10 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन निर्मित कर लेगा।

मालूम हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024–25 तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को 175000 लाख करोड रुपए करना है। वहीं रक्षा निर्यात को बढ़ाते हुए इसी समयावधि में 35000 करोड रुपए से अधिक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने 2020 में 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाई थी। यह उपकरण अब भारत में ही बन रहे हैं। 3700 रक्षा उत्पाद भारत में निर्मित किये जा रहे हैं। 2024 में और 351 सामानों का निर्माण निर्माण भारत में स्वदेशी तकनीक से होने लगेगा। इसरो नासा द्वारा तैयार निसार उपग्रह से समुद्र स्तर, भूजल, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और पृथ्वी में हर घड़ी हो रहे बदलाव की जानकारी मिलने लगेगी। वर्ष 2024 के अंत तक इस मिशन को अंजाम दिया जाना है। इसरो वर्ष 2024 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाया है। मिशन से पहले रोबोट व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। मिशन के लिए वायुसेना के चार पायलटो

स्वावलंबी भारत अभियान के कर्ताधर्ताओं का मानना है कि भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यहां की जनसंख्या जितनी है, उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के लिए जो भी आपूर्ति करता हैं, वह हमारी जरूरत को शायद ही पूरा कर सकते हैं।

की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। भारतीय वायुसेना को इस साल फरवरी में पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस एम के–1ए मिल सकता है। वायु सेवा को कुल 83 जेट मिलने है। इसके लिए एचएएल से 48000 करोड रुपए का करार भी किया गया है।

देश में 5जी लांच होने के बाद 6जी की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा था कि भारत की कोशिश सिक्स जी क्षेत्र का लीडर बनने की है।

स्वावलंबी भारत अभियान के कर्ताधर्ताओं का मानना है कि भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यहां की जनसंख्या जितनी है, उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के लिए जो भी आपूर्ति करता हैं, वह हमारी जरूरत को शायद ही पूरा कर सकते हैं।

दरअसल दूसरे देशों पर निर्भर रहने की कीमत चुकानी पड़ती है जो मौजूदा दौर में हमारे देश के हित में नहीं है। रक्षा, अनाज, कंप्यूटर, मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल है या फिर ऑटोमोबाइल हो, हर तरफ हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब तक भारत जितना भी आत्मनिर्भर बना है वह मात्र असेंबलिंग के क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। भारत को अब सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे कच्चे माल पर चीन या फिर किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता को घटानी होगी। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संयोजक प्रो. अश्वनी महाजन का मानना है कि विगत कुछ वर्षों से कोशिश जरूर हो रही है और इसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। लेकिन जरूरी है कि भारत की क्षमता को देखते हुए यहां शोध पर ज्यादा फोकस किया जाए। अभी जितने शोध हो रहे हैं वह ज्यादातर सरकारी संस्थानों या कंपनियों में हो रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने इस साल ऐसे सामानों की सूची जारी की है जिनका निर्माण भविष्य में देश में ही हो सकेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से उनके आयात पर रोक लगाई जानी चाहिए। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सैकड़ो कल पुर्जे देश में बनने लगे हैं। इससे करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। हर क्षेत्र के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता ही वह कुंजी है जो विश्व पटल पर भारत को आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ताकतवर बन सकती है।

गौरतलब है कि नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए देश में 160480 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर का संचालन हो रहा है। शिक्षा का बाजार जो 2020 में 180 अरब डालर था वर्ष 2030 तक 320 अरब डालर होने की संभावना है। मेक इन इंडिया के तहत देश में 34 बंदे भारत ट्रेन चल रही है। केंद्र की योजना है कि वर्ष 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 75 किया जाना है।

स्वदेशी तकनीक और हमारी युवा मेधा के बदौलत भारत हर दिन प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भारत कई और मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा। ❑❑

आर्थिक केंद्र भी है राम मंदिर

आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण–प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश भर में एक उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति प्राण–प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में जाना चाहता है, यह समझते हुए कि सभी का एक ही समय में अयोध्या में होना संभव नहीं, आने वाले कुछ महीनों में करोड़ों लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बन ही रहा है, दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु होटल और अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण तेज़ी से हो रहा है। इससे न केवल शहर में और इसके आसपास पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह शहर एक क्षेत्रीय विकास केंद्र में बदल जाएगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी के कारण व्यापक क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मानकों का एक मेगा पर्यटक शहर, जो प्रतिदिन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करेगा, पड़ोसी जिलों की अर्थव्यवस्था में भी क्रांति का स्रोत बन सकता है। अयोध्या के लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि पर्यटन का विकास अयोध्या के आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण–प्रतिष्ठा के बाद लगभग 3 लाख की दैनिक उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पवित्र शहर को उन्नत करने हेतु मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अयोध्या का पुनर्विकास 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 10 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था, देश में कुछ लोग यह सुझाव दे रहे थे कि मंदिर के स्थान पर यदि अस्पताल या शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं तो लोगों को फ़ायदा होगा। कांग्रेस शासन के दौरान सरकार के काफी निकट और हाल ही में राहुल गांधी की अमरीका यात्रा में उनके साथ गए एक टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा ने कहा कि मंदिर रोजगार पैदा नहीं करते। स्वभाविक तौर पर वर्तमान में मंदिरों के प्रति आग्रह के संदर्भ में उनकी यह टिप्पणी रही होगी। सैम पित्रोदा चाहे कुछ भी कहें, मंदिरों का अर्थशास्त्र भी समझने की आज बहुत जरूरत है। यह सही है कि कृषि, उद्योग और

आज आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों का विकास करते हुए देश के विकास में इनके योगदान को बढ़ाया जाए।
– स्वदेशी संवाद

सेवाओं का अपना–अपना अर्थशास्त्र होता है, जिसके आधार पर हम देश के विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन मंदिरों के विरुद्ध बोलने वाले लोग भूल जाते हैं कि धार्मिक सेवाओं और मंदिरों का भी अपना एक अर्थशास्त्र होता है। जहाँ मंदिर होते हैं, उसके आसपास विकास कार्य स्वतः ही हो जाते हैं, प्राचीन भारत में हर क्षेत्र को धन लाभ इन्हीं तीर्थस्थलों से होता था। हर मंदिर में आकर्षक शिल्पकला, भव्यता, अलौकिक विग्रहों के कारण यह आध्यात्मिक होने के साथ–साथ पर्यटन स्थल भी थे। यह व्यवस्था सम्पूर्ण भारत में थी।

आज जब मंदिर निर्माण पूर्णता की ओर है और प्राण–प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मंदिर, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन हमारे देश और और जनता के लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं। मंदिरों से भी भारी रोजगार सृजन होता है। मंदिरों के आसपास असंख्य लोग अपना जीवनयापन करते हैं और मंदिरों में भी आधुनिकीकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से न केवल उन सेवाओं के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जीडीपी में भी उनके योगदान में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की ही भाँति मंदिर अर्थव्यवस्था के बारे में भी चिंतन और विचार करना जरूरी है। 20 लाख से भी अधिक मंदिरों वाले भारत देश में 4 करोड़ लोग पर्यटन और यात्रा के उद्योग से सीधे जुड़े हुए हैं। धार्मिक और मंदिर पर्यटन उसका एक बड़ा हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी योजनाबद्ध रूप से इस मंदिर अर्थव्यवस्था को और अधिक पुष्ट करने का कार्य कर रही है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए महाकाल लोक, काशी विश्वेश्वर के लिए काशी कोरिडोर, केदारनाथ में मंदिर जीर्णोद्धार एवं शंकराचार्य स्थल, ओम्कारेश्वर में एकात्म धाम, कश्मीर में शारदा पीठ का जीर्णोद्धार, उत्तराखंड में कैलाश दर्शन का विकास उसी दिशा में कदम हैं।

हम देखते हैं कि आज भी भारत में कई शहरों और कस्बों की एक बड़ी आबादी तो अपनी जीविका के लिए सिर्फ मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर ही निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मथुरा–वृंदावन, अयोध्या, कुशीनगर, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर प्रसिद्ध हैं। यदि हम देखें तो लगभग सभी राज्यों में एक या एक से अधिक बड़े धार्मिक केंद्र हैं। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), रामेश्वरम मंदिर और कई अन्य मंदिर हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी मंदिर; गुजरात में सोमनाथ और द्वारका, पंजाब में स्वर्ण मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। झारखण्ड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर और रांची में जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं; मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत के कई शहरों–क़स्बों में कई मंदिर हैं, जो आस्था के केंद्र हैं।

पर्यटन

जिन शहरों में ऐसे मंदिर स्थित हैं, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सैलानियों का आना होता है। कई स्थान तो ऐसे हैं, जहां एक ही दिन में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। जम्मू के कटरा में स्थित अकेले वैष्णों देवी मंदिर में ही वर्ष 2022 के दौरान 36.4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरूपति बालाजी मंदिर में वर्ष 2022 के दौरान 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी प्रकार से अलग–अलग मंदिरों में करोड़ों लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं। यह स्वभाविक धार्मिक पर्यटन हमारे कुल पर्यटन व्यवसाय का एक बड़ा भाग है, जिससे बड़ी मांग का सृजन होता है। अनुमान है कि भारत में धार्मिक पर्यटन का हिस्सा कुल घरेलू पर्यटन में 60 प्रतिशत है, जबकि 11 प्रतिशत विदेशी सैलानी धार्मिक उद्देश्य से आते हैं। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत है और देश के कुल रोजगार में इसका हिस्सा 8 प्रतिशत है। यानि यह क्षेत्र 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में कुल घरेलू पर्यटन में जहां धार्मिक पर्यटन का योगदान 60 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 11 प्रतिशत होने के कारण मंदिरों के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जहां पिछले वर्ष 2022 में 14.33 करोड़ भारतीय लोगों ने मंदिरों, तीर्थों में भ्रमण किया, वहीं 64.4 लाख विदेशी पर्यटकों ने भी इन स्थानों पर भ्रमण किया। वर्ष 2022 में 1.35 लाख करोड़ की आमदनी इन तीर्थ स्थानों पर हुई। यानि समझा जा सकता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार निर्माण नहीं होता अथवा मंदिरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, उन्हें इन तथ्यों को जानना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों का विकास करते हुए देश के विकास में इनके योगदान को बढ़ाया जाए। इस हेतु मंदिरों का जीर्णोद्धार, सस्ते और महंगे सभी प्रकार के होटलों का निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का विस्तार और इन केन्द्रों में पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना और इन तक पहुंचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ उनका जुड़ाव आदि कुछ ऐसे कार्य हैं, जिसके द्वारा इन तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुष्ट किया जा सकता है। ❑❑

क्यों अमेरिका जाते हैं, सबसे अधिक अवैध अप्रवासी

अमेरिका दुनिया का वह देश है जहां सबसे अधिक अवैध अप्रवासी रहते हैं। अमेरिका की कुल 33 करोड़ की आबादी में 5.2 करोड़ लोग बाहर के देशों से आकर बसे हैं। उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। जर्मनी में ज्यादातर आतंक से भागने वाले शरणार्थी हैं। उसके बाद सऊदी अरब भी एक ऐसा देश है, जहां अच्छी कमाई के लालच में अप्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रूस 11 मिलियन अप्रवासियों के साथ सूची में चौथे नंबर पर आता है और ब्रिटेन 9 मिलियन अप्रवासियों के साथ पांचवें स्थान पर।

भारतीयों के मन में अमेरिकी सपने

कुछ दिन पहले जब यह खबर आई कि अवैध आप्रवासन के संदेह में वैट्री हवाई अड्डे (फ्रांस के पूर्वी मार्ने क्षेत्र में) पर पांच दिन तक लीजेंड एयरलाइंस की उड़ान रोक दी गई और उसके बाद भारतीय यात्रियों से विभिन्न राज्यों में स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ शुरू कर दी गई तो पता चला कि मुख्य रूप से गुजरात और पंजाब के लगभग 300 भारतीय अवैध रूप से निकारागुआ के माध्यम से मैक्सिको की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर तस्करों को लाखों रुपये का भुगतान किया था।

इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं थी प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, 2021 में लगभग 725,000 भारतीय बिना दस्तावेज़ के अमेरिका में रह रहे थे। 2017 के बाद से यह संख्या लगातार बढ़ी है। मैक्सिको और साल्वाडोर के लोगों के बाद भारतीय ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रूप में तीसरा सबसे बड़ा समूह हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2019 के बाद से अमेरिकी सीमाओं में घुसने का प्रयास करने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या दस गुना से अधिक बढ़ गई है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने कथित तौर पर 2022–2023 में 96,917 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की थी, जबकि 2018–2019 में यह संख्या 8,027 थी।

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 1960 के दशक के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या में 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

–विक्रम उपाध्याय

अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के प्रयास में कई हादसे हुए। अप्रैल 2023 में गुजरात का एक परिवार सेंट लॉरेंस नदी में डूबा हुआ पाया गया। कनाडा के पर्यटक वीज़ा पर माता–पिता और उनके दो बच्चों ने अवैध रूप से नदी पार करके अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया था। 2019 में पंजाब की एक 6 वर्षीय लड़की एरिज़ोना रेगिस्तान में मृत पाई गई थी।

अमेरिका में 50 साल में चार गुणा बढ़ गए आप्रवासी

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 1960 के दशक के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या में 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा मेक्सिको के लोग आ कर रह रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 11 मिलियन है। यानि संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा हर चौथा अप्रवासी मैक्सिकन है।

इसका सबसे बड़ा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा एक दूसरे से लगना है। इसलिए मेक्सिको के लोगों का अमेरिका में प्रवेश करना आसान है। अमेरिका एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है इसलिए यह देश दुनिया भर लोगों के लिए आदर्श है। यहाँ आने वाले अधिकतर अवैध अप्रवासी नागरिकता के लिए कानूनी रास्तों को खंगालते रहते हैं।

ग्रीन कार्ड की चाहत

अमेरिका स्थायी निवास वीजा के लिए ग्रीन कार्ड जारी करता है। यूएस की इस ग्रीन कार्ड की मांग काफी अधिक है। स्टैटिस्टा के अनुसार 2007 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति वर्ष लगभग दस लाख लोगों को ग्रीन कार्ड दे रहा है। अब आम अमेरिकी इस नीति से परेशान भी हो रहे हैं और लगातार अवैध नागरिकों को पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी अधिकारियों ने लगभग 1.87 मिलियन अवैध नागरिकों को पकड़ा है।

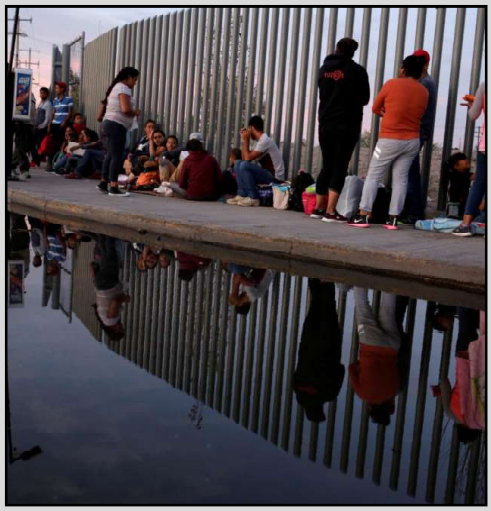

अवैध आप्रवासन ही समस्या नहीं है, बल्कि वहाँ बड़ी संख्या में शरणार्थी भी रहते हैं। अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करना सबसे आसान काम है।

अमेरिका में शरणार्थी

अवैध आप्रवासन ही समस्या नहीं है, बल्कि वहाँ बड़ी संख्या में शरणार्थी भी रहते हैं। अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करना सबसे आसान काम है। खुद को खतरनाक परिस्थितियों में होने और जान का खतरा बताकर अपना देश छोड़ने वालों को नियमित आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है। 2022 में अकेले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगभग 8,000 शरणार्थी आए और अमेरिका ने उन्हें शरण दे दी। 2022 के फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से, अमेरिका ने 2,000 से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी आकर बस चुके हैं।

सऊदी अरब में 40 प्रतिशत तक बाहरी लोग

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार जर्मनी में 16 मिलियन अप्रवासी रहते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग 18.8 प्रतिशत। वहीं सऊदी अरब में 14 मिलियन अप्रवासी रहते हैं, जो कि जनसंख्या का 39 प्रतिशत है। सऊदी अरब की सरकार ने अब जाकर अवैध आप्रवासियों पर लगाम लगाना शुरू किया है।

पिछले साल जुलाई में सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने 1952 के संशोधित सऊदी रेजीडेंसी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नए दंड की घोषणा की थी, जिसके तहत गैर कानूनी तरीके से सऊदी में प्रवेश करने वालों पर 100,000 सऊदी रियाल तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

केवल बाहरी ही नहीं यदि घरेलू प्रबंधक किसी अवैध प्रवासी को नौकरी देते हैं तो एक वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है और यदि प्रबंधक प्रवासी है तो उसका निर्वासन भी हो सकता है। यह दंड उन निजी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जो अपने विदेशी कर्मचारियों को किसी तीसरे पक्ष के लिए काम करने की अनुमति देते हैं।

यही नहीं विदेशी नागरिकों को राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने में सहायता करने पर 5,000 सऊदी रियाल का जुर्माना या पांच महीने की कैद या दोनों दंड मिल सकता है। सऊदी अधिकारियों ने पिछले साल सुरक्षा अभियान के तहत 8,398 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ❑❑

https://hindi.oneindia.com/news/features/illegal-immigration-why-most-illegal-immigrants-go-to-america-870271.html

मजबूत अर्थव्यवस्था में कमजोर होती गरीब की थाली

भारतीय शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का छोटी–मोटी गिरावट के बावजूद 71 हजार के ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर रहना इस बात का संकेत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा कायम है। थोड़े उतार–चढ़ाव के साथ बाजार में चहल–पहल है, बेंचमार्क इंडेक्स का प्रदर्शन भी संतोषजनक बताया जा रहा है लेकिन करीब दो महीने पहले बाजार में आम उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतों में गिरावट की वजह से आम लोगों को जो राहत मिली थी, वह एक बार फिर छिनती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाने–पीने की वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई दर पिछले तीन महीने के उच्च स्तर यानी 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। आटा, दाल, नमक, तेल, चावल आदि के लगातार बढ़ते दामों से कम कमाई पर गुजर–बसर करने वालों का जीवन और अधिक कठिन होता जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बीते अगस्त महीने से खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी आने की वजह से महंगाई दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी। यही कारण है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अक्टूबर के महीने में 4.57 प्रतिशत पर आ गई थी। तब लोगों के मन में यह आस जगी थी कि करोना महामारी के बाद से बाजार में जिन बहुत सारी जरूरत की वस्तुओं तक आम आदमी की पहुंच नहीं हो पा रही थी, उससे अब धीरे–धीरे राहत मिलेगी। बाजार के जानकारों ने भी ऐसी ही भविष्यवाणियां की थी। मगर दुर्भाग्य से यह भाव ज्यादा दिन तक स्थाई नहीं रह सका। अक्टूबर महीने में रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कीमतों में नरमी की वजह से जो आस जगी थी, वह नवंबर में ही छीन गई। दिसंबर के पहले पखवाड़े में बाजारी कारोबार के बढ़ने के चलते शेयर के भाव तो उंचे चढ़ते गए, पर महंगाई डायन भी अपना डायना फैलाने लगी।

वर्तमान में महंगाई दर 5.5 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि यह इधर रिजर्व बैंक की ओर से अधिकतम सीमा के दायरे में ही है, लेकिन यह महंगाई की ओर रेखांकित करने वाली

भारत की सार्थिक उड़ान के पीछे दूरगामी संभावनाओं के साथ–साथ तात्कालिक वैश्विक तथा घरेलू कारक भी हैं। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।
–स्वदेशी संवाद

सीमा रेखा के करीब भी है। मालूम हो कि वस्तुओं की खुदरा कीमतें इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक बड़ी आबादी खाने–पीने तक को लेकर अपने हाथ समेटने लगती है। हालांकि माना जाता है कि ठंड के मौसम की शुरुआत के बाद खासतौर पर बाजार में सब्जियों की आमद बढ़ने की वजह से कीमतों में कमी आती है लेकिन ताजा आंकड़े इसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह सही है कि करीब तीन साल पहले करोना महामारी की वजह से जो हालात पैदा हुए उससे उबरने में देश को काफी समय लगा और अब भी कई क्षेत्र खुद को संभालने की लगातार कोशिश में है। बहुत सारे मामलों में बाजार में सहजता आई है और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने में आया है। निवेशकों के भरोसा के कारण शेयर बाजार की उड़ान इसी का नतीजा है। कमजोर वैश्विक आर्थिक संकेतों के बावजूद भारत में शेयर बाजारों के सूचकांक हौसला देने वाले हैं।

भारत की सार्थिक उड़ान के पीछे दूरगामी संभावनाओं के साथ–साथ तात्कालिक वैश्विक तथा घरेलू कारक भी हैं। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। वैश्विक विकास भले ही सुस्त हो, पर भारतीय बाजार में तेजी के लक्षण हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से दुनिया के निवेशक अब चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। 'भारत में बेचें–चीन में खरीदे' की रणनीति में बदलाव लाते हुए विदेशी निवेशकों ने 'भारत में खरीदे और चीन में बेचे' को तरजीह देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा विदेशी निवेशक विकसित दुनिया के देश खासकर अमेरिका, भारत को चीन प्लस वन नीति का प्रमुख साझेदार मानते हैं। चीज के प्रति बदलती धरना ने भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थागत निवेश (एफपीआई) के प्रवाह को गति दी है। इस वर्ष के पहले दो महीना में लगभग 35000 करोड रुपए के शेयर बेचने वाले एफपीआई बड़े पैमाने पर अब खरीदार बन गए और मई के बाद से अब तक सवा लाख करोड रुपए से अधिक के शेयर खरीदार बन गए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2023–24 के लिए मुद्रा स्फीति 5.1 प्रतिशत अनुमानित है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया अभी भी कमजोर बना हुआ है। अगला साल चुनावी साल है इसलिए मौद्रिक नीतियों के कठोर होने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखने के लिए फौरी कदम उठाने ही चाहिए। इन सबके बावजूद समग्र आर्थिक सूचक भारतीय अर्थव्यवस्था की दूरगामी संभावनाओं की गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं।

अब जबकि आर्थिक स्थितियों में सुधार आने के साथ-साथ औद्योगिक से लेकर खाद्यान्न उत्पादन के स्तर पर भी अच्छी उम्मीदें जगी हैं तब ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि एक प्रतिकूल स्थितियों पैदा होने का संकेत देने वाली है।खास तौर पर खाने-पीने के सामान की कीमतें अगर आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगती है तो इसका सीधा असर उनके बाकी के खर्चों और उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन पर भी पड़ता है।

अब जबकि आर्थिक स्थितियों में सुधार आने के साथ–साथ औद्योगिक से लेकर खाद्यान्न उत्पादन के स्तर पर भी अच्छी उम्मीदें जगी हैं तब ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि एक प्रतिकूल स्थितियों पैदा होने का संकेत देने वाली है। खास तौर पर खाने–पीने के सामान की कीमतें अगर आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगती है तो इसका सीधा असर उनके बाकी के खर्चों और उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। महंगाई के मोर्चे पर तात्कालिक राहत मिलने के बाद उम्मीद के धुंधले होने की वजह कोई छिपी नहीं रही है। खुदरा मुद्रा स्फीति में तेजी के लिए खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। नवंबर महीने से ही खाने–पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है जिसके कारण खाद्य महंगाई दर 8.7 प्रतिशत जा पहुंची है, जो अक्टूबर महीने में 6.61 प्रतिशत थी। सवाल यह है कि अगर महंगाई बढ़ने के लिए इस कारण को चिन्हित किया गया है, तब सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी है? सरकार के संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करने में नाकाम क्यों हो जाते हैं कि बाजार के मांग के अनुपात में जरूरी वस्तुओं खास तौर पर खाने–पीने के सामान की आपूर्ति में सहजता बनाकर रखा जा सके। यह सब जानते हैं कि अगर मौसम में उथल–पुथल से उत्पादन प्रभावित होने या फिर अन्य वजह से बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति कम होती है तो इसका फायदा उठाकर कुछ कारोबारी कीमतों के मामले में मनमानी करना शुरू कर देते हैं। मतलब साफ है कि उत्पादन से लेकर आपूर्ति और बिक्री के स्तर पर उपजने वाली मुश्किल या फिर अव्यवस्था को अगर सही समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो इसका असर वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर ही पड़ता है।❑❑

भारत के लिए पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू काश्मीर का महत्वः
वापसी क्यों आवश्यक?

जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान की धारा 370 तथा 35ए को संसद द्वारा हटाने तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि के पश्चात पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की भारत में वापसी पर राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक पक्षों पर भी जनमानस में और राजनीतिक पटल पर चर्चा होने लगी है।

पाकिस्तान में भी सैन्य नियंत्रित सरकारों की दमनकारी नीतियों, अत्याचारों, मानवाधिकार दमन और शोषण के कारण बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फरबाद तथा सिंध में सरकार विरोधी आंदोलन वर्षों से चल रहे हैं। यह सिलसिला 1947 से ही भारत विभाजन के फलस्वरूप अलग हुए पाकिस्तान में चल रहा है। धरातल पर और पाकिस्तान की घटनाओं के अध्ययन से समझ आता है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, सिंध, पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) कभी पाकिस्तान के साथ एक देश के रूप में आत्मसात नहीं हुए और पाकिस्तान की सेना के बलपूर्वक तथा अत्याचारों के कारण अधिकार में हैं जिसकी परिणति बांग्लादेश की स्वतन्त्रता के रूप में हुई। आतंकवाद, आतंकवादियों और पीओके में उनके लांच पैड से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता त्रस्त है जो भारत में आतंकवाद और आक्रमण और पीओके में जनता के दमन के लिए भी बनाए गए हैं। पाकिस्तान की जनता खुले आम भारत के साथ मिलने की आवाज़ बुलंद करने लगी है। पाकिस्तान की जनता में घोर निराशा है और उस देश की आर्थिक विपन्नता पाकिस्तान के शासकों को ऋण और अनुदानों के लिए दर दर भटकने को विवश कर रही है।

पाकिस्तान से वार्ता के सभी मार्ग लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि पाकितान का नेतृत्व संकट में है। पाकिस्तान एक राजनीतिक दुष्चक्र में फंसा हुआ है जिसका प्रमाण यह है कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार तो है परंतु उसकी डोर सेना के हाथ में है।

– विनोद जौहरी

भारत के दोषपूर्ण और षड्यंत्रकारी विभाजन से जब से पाकिस्तान बना है, तभी से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्धोन्माद ग्रस्त है और आतंकवाद भी उसी का अंग है। कश्मीर को विवादग्रस्त, उद्वेलित तथा आतंकवाद से त्रस्त रखने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी सम्मिलित है और इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें देश विदेश के इतिहासकारों, विद्वानों, सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा राजनीतिक नेताओं द्वारा लिखी गई हैं। रूस तथा चीन के यह आरोप रहे हैं कि कश्मीर को रूस और चीन पर हमले करने के लिए कश्मीर को सैन्य अड्डा और लॉच पैड बनाने का प्रयास किया गया। इन अंतरराष्ट्रीय षडयंत्रों का भयानक घटनाक्रम है जिसके परिणाम जम्मू कश्मीर तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता ने भोगे हैं। सम्पूर्ण पाकिस्तान और विशेषकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुए और उनका सफाया हो गया तथा हिन्दू मंदिरों एवं बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया। यह एक अलग गंभीर विषय है जिस पर अलग से चर्चा की जा सकती है परंतु इसका भी सत्य हम सब के लिए जानना आवश्यक है।

यह जानना और समझना आवश्यक है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का भारत के लिए क्या महत्व है और इसकी भारत में वापसी क्यों आवश्यक है? इस भूभाग को वापस लेने के तर्क को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।

भारत के लिए पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की वापसी क्यों आवश्यक ?

1. अन्य रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के राज्य प्रमुख महाराजा हरि सिंह ने 26

अक्तूबर 1947 को भारत के साथ अपना अधिमिलन कर लिया था। यह अधिमिलन पूर्ण वैधानिक व प्रावधानों के अनुरूप था। अधिमिलन के समय जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। परंतु वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की लगभग 54.4 प्रतिशत भूमि (1 लाख 21 हजार वर्ग किमी.) पाकिस्तान और चीन के अवैध नियंत्रण में है। राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपनी सीमाओं, नागरिकों और संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करके उसे संवैधानिक दायरे में लाये।

2. जम्मू कश्मीर ही भारतीय सभ्यता की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। सदियों से वह भाग भारतीय परंपरा के पदचिन्हों को शैल चित्रों के रूप में सँजोये हुए है। यह सैकड़ों बोलियों और भाषाओं का क्षेत्र है।

3. भारत का यह आर्थिक द्वार है। यह क्षेत्र भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप को स्थल मार्ग से जोड़ता है। भारत को विश्व गुरु व सोने की चिड़िया तभी तक माना जाता था जब भारत की सीमाएं हिंदुकुश व पामीर के पठार को छूतीं थीं। जब भी भारत अपने को महाशक्ति के रूप में देखना चाहेगा तो उसे अपनी इन प्रकृतिक सीमाओं को प्राप्त करना होगा।

4. यह पूरा क्षेत्र भारतीय सभ्यता की पहचान के लिए आवश्यक है, क्योंकि शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि व ज्ञान का केंद्र रहा है। इसी प्रकार भारत अपनी सभ्यता की पहचान सिंधु नदी से ग्रहण करता है जो इस भूभाग से होकर बहती है।

5. चीन की पाकिस्तान के प्रगाढ़ मित्रता कभी संभव नहीं होती यदि गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ होता। यही वह भूभाग है जो इस दोनों को अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। यह गठबंधन वर्तमान में भारत को सबसे अधिक और निकटतम वैचारिक, आर्थिक व रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है।

6. प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपने जन–धन (मानव और भौतिक संसाधनों) की सुरक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है। यहाँ के निवासी मूलतः भारतीय हैं। किसी कारणवश पिछले 75 वर्ष से विदेशी शासन के अधीन आकर दोहरे उपनिवेश का दंश झेल रहे हैं।

7. इस भूभाग को पाकिस्तान के दासता से मुक्त कराना आवश्यक है। इससे पाकिस्तान का आत्मबल क्षीण होगा और पाकिस्तान का वैश्विक इस्लामिक नेतृत्व का भ्रम टूट जाएगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का केंद्र पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू और कश्मीर में किसी युद्ध से भी अधिक जन और धन की हानि हो चुकी है। पिछले 30 वर्षों से भारत एक अप्रत्यक्ष युद्ध में है।

8. रणनीतिक दृष्टि से भी कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए गांधार को सुरक्षित करना होगा। इतिहास की सीख है की भारतीय नेत्रत्व को पानीपत सिंड्रोम से बचना चाहिए, क्योंकि जिन आक्रांताओं को खैबर दर्रे पर रोकना चाहिए था वह पानीपत तक आने में कैसे सफल हुए थे?

9. जैसा कि परिलक्षित हो रहा है कि पाकिस्तान बिखराव की ओर अग्रसर है, इस बिखराव से भारत का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न यह है की क्या भारत इन परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है?

10. किसी भी देश के लिए महाशक्ति की स्थिति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अस्मिता है, उस अस्मिता से जुड़े कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता उस व्यवहार का प्रमुख अवयव है। इस कारण भी भारत को एक निर्णायक फैसला लेने की आवश्यकता है। पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर व लद्दाख वापस लेने का निर्णय भारत को महाशक्ति के रूप में प्रस्थापित करेगा।

भारत के लिए विकल्प खुला है

पाकिस्तान से वार्ता के सभी मार्ग लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि पाकितान का नेतृत्व संकट में है। पाकिस्तान एक राजनीतिक दुष्चक्र में फंसा हुआ है जिसका प्रमाण यह है कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार तो है परंतु उसकी डोर सेना के हाथ में है। सेना मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों में है। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि किस संस्था से विश्वसनीयता के साथ बातचीत की जाए। वास्तव में यह पाकिस्तान के लिए कोई नई स्थिति नहीं है, पहले भी कहा जाता था कि पाकिस्तान को अल्लाह, आर्मी और अमेरिका चलाते हैं। इसलिए कोई भी कूटनीतिक संवाद परिणामोन्मुखी नहीं होंगे, इसका कारण पाकिस्तान की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण अवधारणा है।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर व लद्दाख के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका समाप्त हो चुकी है। शिमला समझौते में यह कहा गया है कि सभी विवादास्पद विषयों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा गया था कि नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखेंगे और कभी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे। लाहौर घोषणा पत्र में भी ईईए शिमला समझौते को दोहराया गया था। पाकिस्तान शिमला और लाहौर समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है। इसलिए भारत के पास शिमला समझौते को मानने की बाध्यता नहीं है। अब भारत के पास अपने मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। ❑❑

(नोट– इस लेख में 'भारत के लिए पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की वापसी क्यों आवश्यक?" के बाद का भाग मूलतः पुस्तक "पाकिस्तान अधिकृत भारतीय भू–भाग जम्मू कश्मीर व लद्दाख" (लेखक श्री शिव पूजन प्रसाद पाठक एवं डा प्रशांत कुमार द्विवेदी – जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, दिल्ली) से साभार लिया गया है।)

स्वदेशी अपनाओ - देश समृद्ध बनाओ

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन-प्रयोग करें
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सँडल, विप्रो–शिकाकाई, फ्रेश, अफगाण, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, वनश्री, सर्वोदय, नीम, अनुरा, अनुस्पा, सर्वोदय, पतंजलि तथा लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ॲक्टो, विमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईज़ी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, पतंजलि, अन्य लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रृंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, बलसारा, जेके, डाबर झंडू, सांडू, बेद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क एवेन्यू, कासवछाप नेचर इसेंस, पतंजलि और लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	बबूल, प्रॉमिस, विको, ओरा, अमर, अँकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, वैद्यनाथ, युवराज, इमामी, पतंजलि, प्रुडंट, विठोबा दंतमंजन तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गॉदरेज, अफगाण, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, वी–जॉन, टोपाज, पनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के., कॉस्मोप्लस तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	साठे, बेकमेन, मोनॅको, क्रेकजैक, गिट्स, शालीमार, पॅरी, रावलगांव, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅमको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विल्स ब्रेड, वेरका, सागर, सपन, प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, शांग्रिला, चॅम्पियन, ॲम्प्रो, पार्ले, पतंजलि तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इस्टंट), डंकन, बह्मपुत्र, एम.आर., शन, टिपस, इंडीया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कन्सोलिडेटेट कॅफे, टाटा–टेटली, अमर–टी और अन्य स्थानीय उत्पादन
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रसना, हमदर्द, मॅप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, स्वीटेंब्लिका, रूह–आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, वेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, उमा, एच.पी.एम.सी उत्पाद, हिम तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
पीने का पानी	बिसलेरी, बैली, नॅचरल, अन्य स्थानीय उत्पादन
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वल्र्ड, गोकूल, अमूल, हिमालय, निरूला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हॅव मोर, वेरका, नेचरल तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	सनफ्लावर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, सनड्राप, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमृत, वनस्पति, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, निरमा नमक, जेमिनी, पतंजलि तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु	विडियोकॉन, बी.पी.एल, ओनिडा, सलोरा, ईटीएण्डटी, टी–सीरीज, नेल्को, वेस्टर्न, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, ऍंकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लू, क्रॉम्पटन, रवी, जय शंकर, कैलाश, श्रीराम, लॉयड्स, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, जीप, नोविनो, ॲम्प्रो, निर्लेप, इलाईट, अंजली, जयको, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, महाराजा, जयपान, प्रेशर कुकर, तृप्ति, आईएफबी, आर.आर. फॅन, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन, फास्ट–ट्रॅक,
लेखन सामग्री	ज़ीफ्लो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कैमल, बिट्टू, प्लेटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी स्टैन्डर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड–टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, बुडलॅनड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
तैयार कपडें	पीटर इंग्लैंड, व्हॅन हुसेन, ॲलेन सॉली, लुई फिलिप, कलरप्लस, मफतलाल, ट्रेंड, केम्ब्रिज, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना, मॉन्टे कार्लो, कॉटन किंग, लिनेन किंग तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन
मोबाईल फोन	माईक्रोमेक्स, कारबॅन, डी–आई और स्थानीय उत्पादन

विदेशी वस्तु त्याग कर - बोलो वन्देमातरम्

वस्तु	विदेशी उत्पादन का बहिष्कार करे।
नहाने का साबुन	लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कैमे, डॅव, पॉड्स, पामऑलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लेसान्सी, जस्मीन, गोस्डमिस्ट, लक्मे, ॲमवे, क्वांटम, मार्गो, फा, नीम
कपड़े धोने का साबुन	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डबल, ट्रीलो, ५०१, ओके, की, रिबेल, ॲमवे, क्वांटम, सर्फ एक्सेल, रिन, विमबार, बिझ, रॉबिन ब्लू, और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्य उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	जॉन्सन, पॉण्ड्स, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एण्ड लवली, वेल्वेट, मेडीकेयर, लेवेंडर, नायसिल, निविया, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीकुरा, लिरिल, लॅक्मे, डेनिम, ऑरगॉनिक्स, पेन्टीन, रूट्स, हेड एण्ड शोल्डर, ॲमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर, ग्लैक्सो, मॉरटिम, लीओरीयल, ट्रेसेमे, लॅक्मे आदि
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	कॉलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मॅक्लीन्स, ॲमवे, क्वांटम, अक्वा फ्रेश, ओरल–बी, फोरहॅन्स, सेन्सोडाइन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	पामऑलिव, निविया, पॉन्डस्, प्लैटिनम, जिलेट, सेवेन–ओ–क्लाक, विलमैन, विल्टेज, इरॅस्मिक, लॅक्मे, डेनिम
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	नेसले, कॅडबरी, बोर्नव्हिटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मैगी, फैरेक्स, अनिकस्प्रे, कॉम्प्लान, किटकैट, चार्ज, एक्लेअर, मॉडर्न ब्रेड, माल्टोवा, व्हिवा, माइलो, मिल्कफूड
चाय कॉफी	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, रेड–लेबल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेबल, टाईगर, नेसकॅफे, नेसले, डेल्का, ब्रू, सनराईज, थ्री फ्लावर्स, ताजा
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	लेहर, पेप्सी, सेवन–अप, मिरींडा, टीम, कोका–कोला, मॅकडॉवेल सोडा, मॅगोला, गोल्डस्पॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स–अप, स्प्रिंट, डयूक्स, फॅन्टा, कॅडबरी, कॅनडा ड्राय, क्रश, कॅडबरी ॲपी
पीने का पानी	ॲक्वाफिना, किन्ले, नेसले नॅचरल
आईस्क्रीम	कॅडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक ब्रांड के उत्पादन, क्वालिटी वॉल्स, कॉरनेली, बास्कीन–रॉबिन्स, यांकी–डूडल्स, कॉरनेट्टो
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा नमक, आटा और चपाती, मॅगी, किसान, तरला, ब्रुक–बॉंड, पिल्सबरी आटा, कैप्टन कुक नमक और आटा, मॉडर्न चपाती, कारगिल आटा, लेज, लेहर, नॉर, मैक्डॉनाल्ड, बर्जर किंग
विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नॅशनल–पैनासोनिक, शार्प, जीई, व्हर्लपूल, सैमसंग, देवू, तोशीबा, एल जी, हिताची, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सानसूई, केनवुड, आइवा, कैरियर, टपरवेयर, जापान लाईफ, ओमेगा, टाइमेक्स, राडो, पायोनियर, व्हर्लपुल
घड़ियां	ओमेगा, टाईमेक्स, टीसीएल
लेखन सामग्री	पार्कर, पायलट, विंडसर–न्यूटन, फैबर–कैसेल, लक्ज़र, बिक, मॉट ब्लैक, कोरस, ॲस, रोटरिंग,
जूते, चप्पल पॉलिश	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी–ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर,
तैयार कपड़े	ली के सभी उत्पाद, बर्लिंगटन, ॲरो, लकोस्ट, सॅनफिस्को, लेविस, पेपे जीन्स, रैंगलर, बेनेटोन, रीड एण्ड टेलर, बायफोर्ड, क्रोकोडाइल
मोबाईल फोन	चीन के सारे उत्पाद, एम–आई, एप्पो, वीवो, सेमसंग, झिओमी, आयफोन, एप्पल

जल संतुलन के लिए जरूरी है तालाबों का पुनरुद्धार

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब पानी संबंधी विभिन्न ज़रूरतें पूरी करने के साथ भूजल स्तर बनाए रखने का मुख्य आधार रहे हैं। हाल के समय में विभिन्न तरह की उपेक्षा के कारण अनेक तालाब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस कारण बढ़े जल संकट के बीच अब उनकी रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास भी होने लगे हैं। विशेषकर बुंदेलखंड में ऐसे प्रयास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां जल संतुलन बनाए रखने में तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लहर ठाकुरपुर गांव (बबीना ब्लॉक, जिला–झांसी) में इसी नाम का विशाल लगभग 87 एकड़ का तालाब आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए गौरवशाली धरोहर रहा है, पर हाल के वर्षों में जलकुंभी, मिट्टी गाद आदि के चलते इसकी सुंदरता और उपयोगिता दोनों कम होती जा रही थी। ऐसे में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने तालाब की स्वच्छता के लिए जनसभा कर अभियान चलाया और प्रशासन से भी संपर्क किया तो उसे काफी सहयोग मिला। मनरेगा के अंतर्गत महीनों तक तालाब की सफाई का अभियान चलाया गया। जलकुंभी और गाद की सफाई की गई तथा नहर का पानी तालाब में लाया गया। आसपास बाड़ लगाई गई और जमीन को पक्का किया गया। हालांकि अभी रोशनी की व्यवस्था और मरम्मत का कार्य होना शेष है, फिर भी तालाब बहुत सुंदर बन गया है। इसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ गई है और पानी साफ हुआ है। गांव वासियों की माने तो एक छोटी नहर निकालकर इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा चंदेल राजाओं के समय से चले आ रहे 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में फैले मानपुर का तालाब जो इसी ब्लॉक में स्थित है में एक छोटी नहर की व्यवस्था पहले से परंपरागत तौर पर रही है। पर आजकल इसमें बहुत टूट फूट हो गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने उस नहर के किनारे भी मरम्मत एवं तालाब की सफाई का काम शुरू किया है। इस कारण गांव वासियों को सिंचाई का बेहतर लाभ मिल रहा है। यह कार्य ऐसे समय में गैर मशीनीकृत पारंपरिक स्वदेशी उपाय से किया गया जब यहां लोगों को रोजगार की बहुत जरूरत थी। खजरा खुर्द गांव में पुराना तालाब नाम से विख्यात तालाब

जल संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तालाबों में पहले से कहीं अधिक जल हो। इसलिए तालाबों की रक्षा एवं वर्षा जल संरक्षण का कार्य अब और महत्वपूर्ण हो गया है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

की उपयोगिता हाल के समय में सफाई न होने के कारण घट गई थी। स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े कुछ साथियों और उनकी महिला कार्यकर्ताओं 'जल–सहेलियों' ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया है। इसके बाद किनारों की मरम्मत, मिट्टी, गाद हटाने, आसपास वृक्षारोपण आदि के कार्य शुरू हुए हैं। तालाब की जल ग्रहण क्षमता बढ़ने के साथ इसके आसपास के कुओं का जलस्तर भी बढ़ा है। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिला के अंगरौठा गांव में महिलाओं ने 107 मीटर की नहर खोदने का कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों में शुरू किया ताकि यहां के सूखे पड़े तालाब में पानी पहुंच सके। बाद में उनके इस साहसिक कार्य से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी सहयोग किया। इसी जिले में गंगा नामक महिला ने अपनी सखियों के साथ एक उपेक्षित सूखे तालाब को फिर से पानीदार बना

देश में बुंदेलखंड जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल संतुलन में तालाबों की विशेष भूमिका है और इनके निर्माण व रखरखाव के लिए परंपरागत तकनीक व सामाजिक तौर तरीके दोनों प्रशंसनीय रहे हैं।

दिया। इस तालाब के बारे में अंधविश्वास प्रचलित था कि जो इसका पुनरुद्धार करेगा उसे हानि होगी। लेकिन गंगा ने लोगों को समझाया कि यह अंधविश्वास है और गांव की प्यास बुझाने का प्रयास इस कारण नहीं रुकना चाहिए। इन महिलाओं ने न केवल तालाब की सफाई की बल्कि इसमें पानी भी पहुंचाया।

देश में बुंदेलखंड जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल संतुलन में तालाबों की विशेष भूमिका है और इनके निर्माण व रखरखाव के लिए परंपरागत तकनीक व सामाजिक तौर तरीके दोनों प्रशंसनीय रहे हैं। इनसे आज भी सीखा जा सकता है। चाहे सभी घरों में नल से जल आ जाए पर इन तालाबों का महत्व बना रहेगा और इनके संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें जमे गाद और मिट्टी को हटाकर इसकी जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करने से किसानों को उपजाऊ गाद मिट्टी अपने खेतों के लिए मिल जाएगी। अनेक स्थानों पर भूजल स्तर पहले से बहुत नीचे चला गया है। यदि बोरवेल आदि से नलों के लिए भूजल का उपयोग किया जाएगा तो ऐसे में जल संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तालाबों में पहले से कहीं अधिक जल हो। इसलिए तालाबों की रक्षा एवं वर्षा जल संरक्षण का कार्य अब और महत्वपूर्ण हो गया है। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

उत्तर प्रदेश में बढ़ता धार्मिक पर्यटन एवं उत्पादों का उपभोग

भारत के आर्थिक विकास को दे रहा गति

भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार को गति देने में कुछ राज्यों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही के समय में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात एवं राजस्थान जैसे राज्यों की आर्थिक विकास की गति तेज हुई है, जिससे यह राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का बनाने में विशेष योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एवं कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता है, परंतु इन राज्यों के आर्थिक विकास की दर तुलनात्मक रूप से कुछ स्थिर सी रही है अथवा कुछ कम हुई है।

समस्त राज्यों के बीच तमिलनाडु एवं गुजरात राज्यों को पीछे धकेलते हुए उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। भारतीय अर्थव्यस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2 प्रतिशत का हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार आज 3.7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है। इसमें महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा 15.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा 9.2 प्रतिशत, तमिलनाडु राज्य का 9. 1 प्रतिशत, गुजरात राज्य का 8.2 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल राज्य का 7.5 प्रतिशत है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर पूर्वी राज्यों एवं जम्मू कश्मीर के बाद बिहार का भी काफी कम योगदान अर्थात केवल 3.7 प्रतिशत दिखाई पड़ता है, जबकि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है। बिहार को आर्थिक विकास की दृष्टि से आज भी पिछड़ा राज्य कहा जा रहा है। पूर्व के बीमारु राज्यों की श्रेणी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य बाहर आ चुके हैं जबकि बिहार राज्य आज भी इसी श्रेणी में अटका हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 41,720 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, तमिलनाडु राज्य का आकार 27,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, गुजरात राज्य का आकार 26540 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, उत्तर प्रदेश राज्य का आकार 26,510 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, कर्नाटक राज्य का आकार 26,350 करोड़ अमेरिकी डॉलर था

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारत के अन्य राज्य भी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सफल होते हैं तो शीघ्र ही भारत की आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत के पार पहुंचाया जा सकता है।

–प्रहलाद सबनानी

और पश्चिम बंगाल राज्य का आकार 18,310 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। पिछले कुछ वर्षों से चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे तेज बनी हुई है अतः आज उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भारत में दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को वर्ष 2027 तक एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि, महाराष्ट्र भी अपने राज्य को वर्ष 2028 तक एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। इस दृष्टि से अब उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच इस संदर्भ में आपस में प्रतियोगिता चल रही है।

महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या 11 से 12 करोड़ के बीच है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य लाभप्रद स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि विभिन्न उत्पादों के उपभोग की अधिक गुंजाइश उत्तर प्रदेश राज्य में हैं एवं देश में आज उत्तर प्रदेश राज्य तेजी से विनिर्माण क्षेत्र का हब बनता जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक पर्यटन भी बहुत तेज गति से विकसित हो रहा है। विशेष रूप से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन को भी आकर्षित करता दिखाई दे रहा है। इससे उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार के नए अवसर भी भारी मात्रा में निर्मित हो रहे हैं। अतः उत्पादों के उपभोग के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य के साथ किसी भी अन्य राज्य की प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक रोजगार हेतु अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ही रोजगार के पर्याप्त नए अवसर निर्मित होने लगे हैं। उत्तरप्रदेश राज्य में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज राज्य सरकार भी भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रही है।

निर्यात के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश राज्य नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश राज्य से 84,000 करोड़ रुपए की राशि का निर्यात किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में दुगना होकर 174,000 करोड़ रुपए का हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दूरसंचार उपकरण, कृत्रिम फाइबर, गेहूं, चावल, कपास, कालीन एवं हस्तशिल्प जैसे उत्पाद शामिल हैं।

दूसरे, उत्तर प्रदेश राज्य आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्स्टायल उत्पादन करने वाला राज्य भी बन गया है। राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का योगदान बढ़कर 13.24 प्रतिशत हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में आज 250,000 लाख के आसपास हैंडलूम बुनकर एवं 421,000 पावरलूम बुनकर कार्य कर रहे हैं। चूंकि कपड़ा उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ अधिक मानवीय आधारित उद्योग है, अतः इस क्षेत्र में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर एवं लखनऊ उन्नाव कानपुर क्षेत्र में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कलस्टर भी स्थापित किये जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं में प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2022–23 के आर्थिक सर्वेक्षणों में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इन प्रदेशों की अनुमानित आर्थिक प्रगति की दर को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर्थिक प्रगति की दर 16.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 16.34 प्रतिशत, राजस्थान में 16.4 प्रतिशत, गुजरात में 15.5 प्रतिशत, तेलंगाना में 15.6 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 6.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 8.19 प्रतिशत, बिहार में 9.7 प्रतिशत, कर्नाटक में 7.9 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 19 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कुल मिलाकर भारत के समस्त प्रदेशों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य आज आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्य भी विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन राज्यों की आर्थिक नीतियां देशी एवं विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस प्रकार यह समस्त राज्य मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यदि बिहार जैसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना की तर्ज पर एवं पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अन्य छोटे राज्य भी अपने राज्यों में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सफल होते हैं तो शीघ्र ही भारत की आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत के पार पहुंचाया जा सकता है। ❑❑

प्रहलाद सबनानी– सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

भगवान श्री राम का पर्यावरण प्रेम

प्रकृति, पर्यावरण, प्रगति के मध्य अन्तः संबंध है जिनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण सांस्कृतिक विरासत से निर्मित एवं विकसित होता है और इस संदर्भ में भारतीय हिन्दू संस्कृति की वैश्विक भूमिका प्राचीनकाल से ही महत्वपूर्ण मानी गयी है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण संरक्षण हिन्दू संस्कृति के अभिन्न अंग रहे है। बाल्मीकि रचित रामायण से लेकर तुलसीदास रचित रामचरित मानस में प्रकृति चित्रण पर्यावरण संचेतना, पर्यावरण संरक्षण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। वास्तव में हिन्दू धर्म एक विशिष्ट पूजा पद्धति, आस्था तक ही सीमित नहीं है वरन जैसा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिन्दू धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि हिन्दू धर्म एक जीवन शैली है। हिन्दू धर्म की इस जीवन शैली में धर्म तथा पर्यावरण में सह–सम्बन्ध माना गया है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रकृ ति के साथ मानव द्वारा उचित, संवेगात्मक एवं सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध निभाना ही उसका धर्म है। पृथ्वी को धरती माता के रूप में पूजित माना गया तथा सूर्य,जल,वायु,वृक्ष, अग्नि सभी को देवता मानकर पूजनीय माना गया केवल यही नहीं विभिन्न देवी–देवताओं के वाहक के रूप में विभिन्न पशु–पक्षियों की भी आराधना की पद्धति विकसित की गयी। जल, वायु को दूषित करना, वृक्षों का अनावश्यक रूप से कटाव करना को पाप माना जाता था, क्योंकि उस समय ऋषि, मुनियों को पर्यावरण के इन महत्त्वपूर्ण घटकों के महत्त्व का ज्ञान था। तत्त्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन में पर्यावरणीय तत्त्वों के साथ सामंजस्य की भावना धर्म से जुड़ी हुई थी।

लेकिन पाश्चात्य भौतिकवाद की अवधारणा पर आधारित प्रगति के स्वरूप एवं दिशा ने आज इक्कीसवीं शताब्दी में पर्यावरण प्रदूषण के रूप में मानव जाति के अस्तित्त्व को ही चुनौती प्रस्तुत कर दी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ओजोन परत में छिद्र, अम्लीय वर्षा इत्यादि का अत्यन्त विनाशकारी स्वरूप बुद्धिजीवी, विवेकशील, वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बन चुके है। लम्बे समय

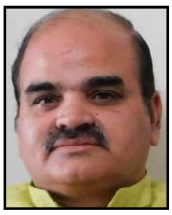

जब मनुष्य पृथ्वी का संरक्षण नहीं करता, तो पृथ्वी भी अपना गुस्सा कई प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाती है। वह दिन दूर नहीं, जब हमें शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, उपजाऊ भूमि, शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध वनस्पतियां नहीं मिल सकेंगी। इन सबके बिना जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा।

– डॉ. राजीव कुमार

तक भौतिक विकास के विनाशकारी मद में मदोन्मत्त लोगों की सुप्त पर्यावरण चेतना अब जागृत हो रही है तथा इस भौतिकवादी प्रगति के पुरोधा भी पर्यावरण संरक्षण की बात करने लगे है। मानव समाज किस समय कौन सी समस्या से ग्रस्त होता है और उसके निदान के लिए समाज के सदस्यों की भूमिका एवं सहभगिता एवं शासकीय प्रयासों की तुलना में अधिक उस समाज के सांस्कृतिक मूल्य अधिक प्रभावी होते हैं। इस संदर्भ में भारतीय संस्कृति के आधार पुरातन ग्रन्थ–वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण के साथ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस का अध्ययन व विश्लेषण अत्यन्त लाभप्रद हो सकता है विशेषकर रामचरित मानस का क्योंकि वर्तमान समय में घर–घर में न केवल रामचरितमानस एक पवित्र ग्रन्थ के रूप में पूजा जाता है वरन इसका पाठ पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर किया जाता है।

जब हम अपने किसी मित्र या संबंधी से मिलते हैं तो सभी का हालचाल पूछते हैं किसी से मिलकर हम उसके बच्चों, परिवार आदि की ही कुशलक्षेम पूछते हैं। हम सबने कभी सोचा ही नहीं कि किसी का हालचाल पूछते समय उस क्षेत्र के वनों, नदियों, तालाबों या वन्यजीवों का समाचार जानने की चेष्टा करें। ऐसा इसलिए है कि अब हम वनों, नदियाँ, तालाबों या वन्यजीवों को परिवार का अंग मानते ही नहीं। पहले ऐसा नहीं था। उस समय लोग एक दूसरे का समाचार पूछते समय वनों, बागों, जलस्रोतों आदि की भी कुशलता जानना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उस समय लोग प्रकृति के विभिन्न अवयवों को परिवार की सीमा के अन्तर्गत ही मानते थे। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण चित्रकूट में राम भरत मिलन के समय मिलता है। श्रीराम अपने दुखी भाई भरत से पूछते हैं कि उनके दुखी

होने का क्या कारण है? क्या उनके राज्य में वन क्षेत्र सुरक्षित हैं? अर्थात वन क्षेत्रों के सुरक्षित न रहने पर पहले लोग दुखी एवं व्याकुल हो जाया करते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित उदाहरण निम्न प्रकार है–

कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः।
कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुन्जराणां च तृप्यसि।।

जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं न? तुम्हारे पास दूध देने वाली गाएँ तो अधिक संख्या में हैं न? (अथवा हाथियों को फँसाने वाली हथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है?) तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? अनेक स्थानों पर वाल्मीकि जी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। श्री भरत जी अपने सेना एवं आयोध्या वासियों को छोड़कर मुनि के आश्रम में इसलिये अकेले जाते हैं कि आस–पास के पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे।

श्रीराम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मन्द गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था।

तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि उस समय में पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। काफी बड़े भू–भाग पर वन क्षेत्र विद्यमान थे। वन क्षेत्रों में ही ऋषियों एवं मुनियों के आश्रम थे, जो उस समय ज्ञान–विज्ञान का केन्द्र थे। समाज में इन ऋषि–मुनियों का बड़ा सम्मान था। बड़े–बड़े राजा महाराजा भी इन मनीषियों के सम्मान में नत मस्तक हो जाते थे। श्रीराम को वनवास मिलने के उपरान्त सर्वाधिक प्रसन्नता इसी बात की हुई कि वन क्षेत्र में ऋषियों का सत्संग का लाभ प्राप्त होगा।

प्रभु श्रीराम को आने वाले समय में रामराज्य की स्थापना करनी थी, जिसमें सभी सुखी हो सकें इसलिये स्वाभाविक ही था कि उन्होंने लम्बे समय तक ऋषि–मुनियों के सानिध्य में रहने का निर्णय लिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर वन क्षेत्रों का सजीव वर्णन किया है। वन क्षेत्र घनी आबादी से दूर स्थित होते थे तथा इन क्षेत्रों में भोली–भाली आदिवासी जनता रहती थी। श्रीराम ने इन भोले–भाले लोगों से प्रगाढ़ मित्रता स्थापित की और जीवनपर्यन्त उसका निर्वहन किया। निषादराज केवट,

वानरराज सुग्रीव एवं गिद्धराज जटायु इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। वनवासी बन्दरों से राम की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। इन्हीं बन्दर–भालुओं की सहायता से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की उपेक्षित गिद्ध जटायु को श्रीराम ने अत्यधिक सम्मान दिया। श्रीराम के सानिध्य से अंगद, हनुमान, जामवन्त, नल, नील, सुग्रीव, द्विविद, आदि भालू कपि तथा जटायु जैसे गिद्ध सदा के लिये अमर हो गये। पूरे रामचरित मानव में हम पाते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को उपभोग मात्र की वस्तु नहीं माना गया है। बल्कि सभी जीवों एवं वनस्पतियों से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित किया गया है। प्रकृति के अवयवों का उपभोग निषिद्ध नहीं है। उनके प्रति कृतज्ञ होकर हम आवश्यकतानुसार उस सीमा तक उपयोग कर सकते हैं जब तक किसी अवयव के अस्तित्व पर संकट न आए। कोई भी प्रजाति किसी भी दशा में लुप्तप्राय नहीं होनी चाहिये।

भगवान श्रीराम ने प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति को बचाने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्रीराम वनवास काल में जिस पर्ण कुटीर में निवास करते थे वहां पांच वृक्ष पीपल, काकर, जामुन, आम व वट वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर श्रीराम–सीता भक्ति आराधना करते थे। अनेक स्थानों पर तुलसीदासजी एवं वाल्मीकिजी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। रामराज्य पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न एवं स्वर्णिम काल था। मजबूत जड़ों वाले फल तथा फूलों से लदे वृक्ष पूरे क्षेत्र में फैले हुये थे। श्रीराम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मन्द गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। इसलिए जो कुछ हम सब रामायण से समझ पाते हैं, वह ही मनुष्य के जीवन जीने की सनातन परंपरा है। वही परंपरा ही हम सबको यह बताती है कि प्रकृति रामराज्य का आधार है।

हम श्रीराम तो बनना चाहते हैं पर श्रीराम के जीवन आदर्शों को अपनाना नहीं चाहते, प्रकृति–प्रेम को अपनाना नहीं चाहते, यह एक बड़ा विरोधाभास है। अजीब है कि जो हमारे जन–जन के नायक हैं, सर्वोत्तम चेतना के शिखर हैं, जिन प्रभु श्री राम को अपनी सांसों में बसाया है, जिनमें इतनी आस्था है, जिनका पूजा करते हैं, हम उन व्यक्तित्व से मिली सीख को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। प्रभु श्रीराम ने तो प्रकृति के संतुलन के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया। अपने–पराए किसी भी चीज की परवाह नहीं की। प्रकृति के कण–कण की रक्षा के लिए नियमों को सर्वोपरि रखा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पर हमने यह नहीं सीखा और प्रकृति एवं पर्यावरण के नाम पर नियमों को तोड़ना आम बात हो गई है। प्रकृति को बचाने के लिये संयमित रहना और नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते।

यही कारण है कि जब मनुष्य पृथ्वी का संरक्षण नहीं कर पा रहा तो पृथ्वी भी अपना गुस्सा कई प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखा रही है। वह दिन दूर नहीं होगा, जब हमें शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, उपजाऊ भूमि, शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध वनस्पतियाँ नहीं मिल सकेंगी। इन सबके बिना हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा। निश्चित ही इन सभी समस्याओं का समाधान श्रीराम के प्रकृति प्रेम में मिलता है, श्रीराम के मन्दिर का उद्घाटन निश्चित ही रामराज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होने का दुर्लभ अवसर है, इस अवसर पर हमें श्रीराम के प्रकृति–संरक्षण की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए देश ही नहीं, दुनिया की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं सृष्टि–असंतुलन की समस्याओं से मुक्ति पानी चाहिए। ❑❑

लेखक– अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख,
स्वदेशी जागरण मंच

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

अखिल भारतीय वृहद बैठक

कन्याकुमारी (23–25 दिसंबर 2023)

– स्वदेशी संवाद

युवा, उद्यमिता एवं स्वदेशी के वृहद विचार पर केन्द्रित स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान की अखिल भारतीय वृहद बैठक 23, 24, 25 दिसंबर 2023 को विवेकानद केंद्र (कन्याकुमारी) में 13 सत्रों में संपन्न हुई। बैठक में देश के 42 प्रांतों से प्रांतस्तरीय एवं इससे ऊपर के दायित्ववान 274 कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। जिसमें 48 मातृशक्तियों ने भी भाग लिया।

बैठक के उपरान्त दो दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण बैठक में 25 प्रांतों के 40 पूर्णकालिक कार्यकर्ता उपस्थित रहें। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक पर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

प्रथम सत्र (उद्घाटन सत्र) – 23 दिसंबर

उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह एवं वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय भागैय्या जी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विवेकानंद केन्द्र के प्रमुख श्री बालकृष्ण जी एवं महासचिव श्री भानुदास जी तथा जोहो कारपोरेशन के चेयरपर्सन एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संरक्षक श्री श्रीधर वेम्बू का भी विशेष सानिध्य इस सत्र में प्राप्त हुआ। मंच पर अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम, राष्ट्रीय सगंठक श्री कश्मीरी लाल, अ.भा. सह संयोजक एवं अभियान के अ.भा. समन्वयक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, डॉ. धनपतराम अग्रवाल, डॉ. अश्वनी महाजन, महिला कार्यप्रमुख श्रीमती अमिता पत्की उपस्थित रहे।

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने स्वावलंबी भारत अभियान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जनवरी 2022 में अपनी प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में हुई। वर्तमान में स्वावलंबी भारत अभियान के 400 रोजगार सृजन केंद्र एवं 152 पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरे देश में कार्यरत हैं। वर्तमान में 94 कार्यकर्ताओं की केंद्रीय टोली है, जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि स्वदेशी सप्ताह व बाबू गेनू बलिदान दिवस संपूर्ण देश में वृहद रूप से मनाया गया, जो आगामी वर्षों में भी इसी रूप में मनाया जाना चाहिए। स्वदेशी, विदेशी एवं स्थानीय वस्तुओं की जानकारी वाले पत्रक बांटना अनिवार्य कार्य है। स्वदेशी मेलों का आयोजन

स्थान–स्थान पर होना चाहिए। स्वदेशी शोध संस्थान के भवन का कार्य अंतिम चरण में है तथा 9 अप्रैल (नववर्ष प्रतिपदा) तक अतिरिक्त कार्य भी पूरा होकर लोकार्पण हो जाएगा।

श्री श्रीधर वैम्बू ने जिला आधारित अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विश्व में चीन द्वारा स्थापित आर्थिक मॉडल स्थान बना रहा है। यह मॉडल युवाओं को मात्र 5–7 वर्ष के लिए 18–20 हज़ार का रोज़गार देकर जीवन के प्रति उनके समूचे दृष्टिकोण को समाज से विरक्ति में बदल देता है, उन्हें एकाकी बना देता है, जो किसी भी राष्ट्र के उत्थान में कभी भी सहायक नहीं हो सकता। उन्होंने तमिलनाडु के एक जिले में एक विदेशी कंपनी द्वारा कर्मचारी के रूप में रखी गई 35,000 महिलाओं का उदाहरण दिया, इस विदेशी कंपनी में काम करने के फलस्वरुप जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य बदल रहे हैं, जन्म दर घट रही है, साउथ कोरिया में तो यह 0.7 की रह गई है। हमें ऐसे आर्थिक विकास मॉडल को बदलना है ।

माननीय भगैय्या जी ने अपने प्रेरणादायक उद्‌बोधन में स्वदेशी को ही जीवन की दृष्टि और जीवन शैली बताया। स्वदेशी जागरण मंच का प्रथम कार्य स्वदेशी की संकल्पना को जन–जन तक पहुंचाना है। युवाओं के मध्य स्वदेशी और स्वावलंबन की ओर जाने की राह प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक गाय के पालन से 20,000 रुपए प्रतिमाह कमाये जा सकते है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वदेशी जागरण के कार्यकर्ताओं के मानसिक, सामाजिक उत्थान, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना एवं उनके प्रशिक्षण की आवश्कता पर बल दिया। पंच प्रवाह में स्वदेशी का विषय अति महत्वपूर्ण है, जिसे जीवन में उतारने की महती आवश्यकता है। स्वदेशी की भावना में ही विश्व का कल्याण है।

श्री आर. सुंदरम ने कहा कि कन्याकुमारी का यह स्थान बहुत ऊर्जावान है। विवेकानंद केंद्र का महत्व बताया और साथ ही इस स्थान पर आयोजित बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया।

अखिल भारतीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक भारत@2047 का विमोचन भी मंचासीन महानुभावों द्वारा किया गया। सत्र का संचालन अ.भा. सह–संयोजक श्री अजय पत्की द्वारा किया गया।

सत्र–2

इस सत्र में 6 क्षेत्रों (दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र व उत्तर क्षेत्र) के अनुसार गत वर्ष में संपन्न कार्यों का वृत्त निवेदन क्षेत्र संयोजकों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि डॉ राजीव सिजारिया ने पूरे देशभर में विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलनों की जानकारी दी।

सत्र का संचालन अखिल भारतीय संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री अनन्दा शंकर पाणिग्रही ने किया।

सत्र–3

इस सत्र में शेष 5 क्षेत्रों, जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, बिहार–झारखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र (उड़ीसा, बंगाल) एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यवृत्त क्षेत्र संयोजक/समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत किए गए।

सहकार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोर ने सहकारिता से स्वरोजगार विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्ट्रॉबेरी खेती के उदाहरण द्वारा सहकार भारती के सहयोग से प्रकल्प खड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में तहसील स्तर पर महिलाओं द्वारा कंज्यूमर स्टोर चलाये जा रहे है। ऑल इंडिया लेवल पर आई.टी. की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने एवं उत्तर प्रदेश में एस.एच.जी. के माध्यम से महिलाओं द्वारा दंत मंजन निर्माण एवं लिज्जत पापड़ का उदाहरण भी दिया।

डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन समझौतों के माध्यम से हुए विदेशी षडयंत्र से देश को बचाना रहा है। एक नेरेटिव स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बनाया गया कि डब्ल्यू.टी. ओ. के समझौतों को हम नहीं मानेंगे, जनता के साथ गलत नहीं होने देंगे, समझौते के लिए आंदोलन किया गया, जिसका ही परिणाम था कि भारत सरकार ने पेटेंट को विदेशी दबाव के बावजूद मानने से मना कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि विदेशी ताकतों द्वारा भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। जैसे– भारत एक अल्प विकसित, गरीबी, भुखमरी वाला देश है। लेकिन वर्तमान में इस भ्रामक प्रचार को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी बढ़ने का अर्थ किसी भी देश का विकास होना नहीं हो सकता।

स्वावलंबी भारत अभियान में सहयोगी 'दे आसरा फाउंडेशन' के प्रतिनिधि श्री आशीष पंडित ने बताया कि यह फाउंडेशन अब तक 2,75,000 उद्यमियों का सहयोग कर चुका है। अभियान के साथ मिलकर भविष्य की कार्य योजना के बारे में स्पष्ट किया।

सत्र का संचालन डॉ राजकुमार मित्तल (वर्तमान में अखिल भारतीय सह–संयोजक) ने किया।

सत्र–4

यह सत्र गटशः हुआ। सभी 11 क्षेत्रों को पाँच गटों में विभाजित कर तीन विषय संबंधित अधिकारियों द्वारा रखे गये। 1. भारत @ 2047, 2. स्वदेशी मेला, 3. 12 जनवरी की युवा उद्यमिता रैली। सभी 11 क्षेत्रों ने विषयों पर चर्चा कर अपनी–अपनी कार्य योजना बनाई।

सत्र–5

यह सत्र क्षेत्रशः बैठकों का रहा, जिसमें सभी प्रांतों ने अखिल भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अपने क्षेत्रानुसार बैठक कर निम्न विषयों पर चर्चा एवं योजना बनाई। 1. पूर्णकालिक कार्यकर्ता, 2. संगठनात्मक विस्तार व 3. प्रवास योजना।

सत्र–6 (24 दिसंबर 2023)

इस सत्र का विषय 'स्वावलंबी भारत अभियान एवं हमारी कार्य पद्धति' रहा। सत्र में श्री सतीश कुमार ने कहा कि देश को विकास के पथ पर लेकर जाने एवं स्वावलंबी बनाने का प्रथम सूत्र युगदृष्टा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय ही दिया था। आज 'Nation First, Swadeshi must' का नारा स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से स्वदेशी के मूल भाव का ही प्रत्यक्ष विस्तार है। स्वदेशी, सहकारिता, उद्यमिता और विकेंद्रीकरण के चतुष्पंक्ति मार्ग के माध्यम से देश को रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त, समृद्धियुक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें भाव जागरण, मानसिकता परिवर्तन के लिए संकल्पित होकर, संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

स्वाभाविक रूप से हमारे पास "संस्कार–उद्देश्य की पवित्रता–उद्देश्य की व्यावहारिकता–दृढ़ निश्चय" अवश्य है, जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यह सत्र चर्चात्मक था, जिसमें प्रश्नोत्तरों का क्रम भी रहा। सत्र का संचालन अ.भा. सह व्यवस्था प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने किया।

सत्र–7

इस सत्र में सर्वप्रथम अ.भा. सह–संयोजक डॉ धनपतराम अग्रवाल ने अपनी विषय प्रस्तुति में बताया कि वर्तमान में भारत जीडीपी अनुसार विश्व की पाचंवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें दो बातों को ध्यान में रखकर आगे बढना चाहिए, पहला– पर्यावरण और दूसरा– भौतिक संपदा। वर्तमान में भारत की कार्यशील जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, परन्तु समृद्धशाली राष्ट्र बनने के लिये हमें टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ना होगा, नए अनुसंधान व अविष्कार करने होंगे।

श्री हार्दिक सोमानी ने स्वावलंबी भारत अभियान के डिजिटल स्वरूप माई–एसबीए के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माई–एसबीए प्लेटफार्म के माध्यम से जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों ही सरलता से अपना पंजीकरण कर सकते हैं, और रोजगार सृजन के अवसरों की जानकारी के साथ जुड़ सकते है। 12 जनवरी से एसबीए वालंटियर बनाने का अभियान प्रारंभ करना है, प्रत्येक जिले में न्यूनतम 1000 वालंटियर बनाने का लक्ष्य लिया गया है।

श्री ज्वाला प्रसाद (विद्या भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य) ने बताया कि भारतवर्ष में विद्या भारती एक मात्र ऐसी गैर सरकारी संस्था है जिसके द्वारा देश भर में 28,000 विद्यालय संचालित किए जाते हैं। गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति और विद्या भारती के द्वारा अभियान को किस प्रकार गति दी जा रही हैं, इसका भी उल्लेख किया। इन विद्या मंदिरों में युवाओं के लिये रोजगार एवं उद्यमिता के कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

डॉ. धर्मेंद्र दुबे (अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख) ने प्रचार तंत्र के विषय में बताया कि प्रांत स्तर पर प्रचार टोली में न्यूनतम पांच कार्यकर्ता और जिला स्तर पर न्यूनतम तीन कार्यकर्ता होने चाहिए, संगठनात्मक प्रचार–प्रसार करने के लिए मंच एवं अभियान सोशल मीडिया एकाउंट्स को स्वयं भी फॉलो करें व इसके फॉलोअर्स बढ़ाएं। इंस्टाग्राम पर माई–एसबीए और ज्वाइन स्वदेशी के नाम से अकाउंट है। फेसबुक पर जॉइन स्वदेशी और यूट्यूब पर भी जॉइन स्वदेशी, एक्स (टविट्र) पर स्वदेशी योद्धा के नाम से अकाउंट है।

स्वदेशी पत्रिका के लिए सदस्यता अभियान एवं डिजिटल स्वरूप के लिए भी सदस्यता शुल्क 50 रू. लेकर डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।

डॉ अश्वनी महाजन ने कहा कि देश के अंदर देश विरोधी ताकते अपना सर उठा रही है, जिसे प्रचार के माध्यम से कमजोर किया जा सकता है। हमें संगठन में समवैचारिक, बुद्धिजीवियों को जोड़ना चाहिये। सत्र का संचालन अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख डॉ राजकुमार चतुर्वेदी ने किया।

सत्र–8

श्री सतीश चावला (अ.भा. वित्त प्रमुख) ने वित्त संबंधी विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून 2023 को अर्थ संग्रह अभियान आरंभ किया गया था। इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से कैशलैस और पेपरलैस उपक्रम है। जिला स्तर तक अभियान के प्रत्यक्ष और सफल संचालन हेतु अर्थ की आवश्यकता रहेगी, जिसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अर्थ संग्रह करके ही सरल किया जा सकेगा। सीएसआर, संस्थागत एवं व्यक्तिगत तीनों प्रकार से हम योगदान ले सकते हैं। जितना धन संकलित होगा उसमें से 85 प्रतिशत

जिला का, 10 प्रतिशत प्रांत का, और 5 प्रतिशत केंद्र का हिस्सा होगा। इस वर्ष धन संग्रह अभियान अप्रैल माह में किया जाएगा। प्रो. प्रदीप चौहान (जेएनयू) ने स्वदेशी शोध संस्थान की प्रगति के बारे में बताया।

श्री रवि कवि ने इंटरप्रिनोयर चेंपियनशिप अवार्ड के सम्बंध में एक डोक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया, जो कि मार्च के प्रथम सप्ताह में भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित होने वाला है। इसके उपरांत सभी प्रांतों और जिलों में भी उद्यमिता अवॉर्ड की योजना को लागू किया जाये, ऐसा विचार सभी के समक्ष रखा गया।

अ.भा. सह व्यवस्था प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने परिसंपतियों के संबंध में एवं केंद्रीय कार्यालय प्रमुख श्री लक्ष्मण भावसिगंका ने कार्यालय के संबंध में जानकारी दी। सत्र का संचालन डॉ एस. लिगामूर्ति ने किया।

सत्र– 9

इस सत्र में श्री शशांक मणि त्रिपाठी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में जाग्रति उद्यम केंद्र एवं युवा जाग्रति यात्रा का संचालन करते हैं, ने उद्यमिता के संबंध में युवाओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने पर बल दिया। नेशनल इंटरप्रिनोयरशिप सर्विस का प्रचलन बढ़ाना होगा, ताकि युवा पीढ़ी को पर्याप्त जानकारी एवं मार्गदर्शन मिल सके और उनके मन–मस्तिष्क में उद्यमी बनने के गुणों का विकास हो।

श्री सुरेन्द्रन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, ने बताया कि 2 करोड़ सदस्यों के साथ भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। कोरोना महामारी के बाद आजीविका का महत्व अधिक समझ में आया है, सगठन सरकारी, गैर सरकारी, सगठित एवं असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये सतत् प्रयत्नशील है। सत्र का संचालन डॉ सुनीता भरतवाल ने किया।

सत्र– 10

'पूर्ण रोजगारयुक्त भारत, समद्ध भारत' विषय पर आधारित इस सत्र में विविध संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तरंग माध्यम से जुड़कर उनके संगठनों में रोजगार सृजन की गतिविधियों पर चर्चा हुई। जिसमें विश्व हिन्दू परिषद, सेवा भारती, ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, हिन्दू जागरण मंच, सक्षम, पर्यावरण गतिविधि, भारतीय शिक्षण मण्डल, गायत्री परिवार, वक्रांगी ग्रुप, आईआईडी इत्यादि प्रमुख रहें। श्री आर. सुन्दरम, श्री सुरेन्द्रन, प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, श्री श्याम मनोहर मंचासीन रहे। डॉ भगवती प्रकाश शर्मा ने विषय पर प्रकाश डाला। सत्र का संचालन अभियान के सह समन्वयक श्री जितेन्द्र गुप्त ने किया।

सत्र– 11 (24 दिसंबर 2023)

इस सत्र में महिला कार्य एवं अभियान का आगामी कैलेंडर पर चर्चा हुई। श्रीमती अर्चना मीना (अ.भा. महिला सह समन्वयक) ने स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र से जिला स्तर तक महिलाओं की अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी, तंत्र समन्वय, डिजिटल प्लेटफार्म का पूर्ण उपयोग विषय पर जानकारी रखी।

श्रीमती अमिता पत्की ने कहा कि हर परिवार की मानसिकता, आर्थिक स्थिति अलग–अलग होती है, इसलिए हमें अपनी रचनात्मकता से तय करना है कि स्वदेशी का विस्तार कैसे परिवारों तक करें। उन्होंने इस विषय पर प्रभावी उदाहरणों के द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

डॉ. राजीव कुमार (अ. भा. सह समन्वयक) ने आगामी वर्ष 2024 (जनवरी से दिसंबर) का कार्यक्रमों का वार्षिक कलेण्डर विस्तार से सबके सामने रखा। सत्र का संचालन डॉ प्रतिभा चतुर्वेदी ने किया।

सत्र –12

प्रो. राजकुमार मित्तल ने "ब्रेन ड्रेन एंड ब्रेन गैन" जो भारतीय विदेशों में हैं, जब वे भारत वापस आएंगे तो उनका संपर्क/अनुभव/अर्थ भारत के काम आयें, इस पर प्रभावी ढंग से विषय सबके समक्ष रखा।

श्री एस. लिंगामूर्ति (क्षेत्र समन्वयक) ने मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पर बताया कि "सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ" भारत में 1500 तक 21000 उत्सव मनाये जाते थे और उत्सवों से ही प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार मिल जाता था। उदाहरण– मुंबई, हैदराबाद का गणेश उत्सव, बंगाल का दुर्गा उत्सव इत्यादि। देश के ऐसे स्थानों को चिन्हित करना और वहाँ रोजगार सृजन की उचित योजना बने।

श्री कश्मीरी लाल ने संगठन एवं कार्यकर्ता विषय पर कहा कि कार्यकर्ता पैदा नहीं होता, बनाना पड़ता है। कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष, कार्यालय इन चार बातों पर उदाहरणों के साथ प्रभावी विषय रखा। रोज़गार सृजन केंद्र को स्वदेशी का कार्यालय बनायें, साथ ही कार्यकर्ताओं के पाँच करणीय कार्य बताये। सत्र का संचालन डॉ धर्मेन्द्र दुबे ने किया।

सत्र–13 (समापन सत्र)

श्री भानुदास (महामंत्री, विवेकानंद केन्द्र) ने विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केन्द्र का विस्तृत इतिहास पटल पर रखा। श्री सतीश कुमार ने 'भारतीय युवा की जीवन शैली–उद्यमिता विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाला समय भारत का है। आने वाले दिनों में उद्यमिता भारत के युवाओं की जीवन शैली बनने वाली है। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता, जिसका समय आ गया हो।

अ.भा. संगठक श्री कश्मीरी लाल ने अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम की ओर से नवीन दायित्वों की घोषणायें की।

नवीन दायित्व

अखिल भारतीय दायित्व

- श्री अरुण ओझा, बिहार–झारखण्ड क्षेत्र के पालक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य।
- प्रो. राजकुमार मित्तल, अ.भा. सह–संयोजक (पूर्व में अ. भा. विचार विभाग प्रमुख)
- डॉ. राजीव कुमार, अ.भा. विचार विभाग प्रमुख (पूर्व में अ.भा. सह विचार विभाग प्रमुख) तथा स्वावलम्बी भारत अभियान के अ.भा. सह–समन्वयक।
- श्री धर्मेंद्र दुबे, अ.भा. प्रचार प्रमुख (पूर्व में अ.भा. सह–प्रचार प्रमुख)
- प्रो. राघवेंद्र चन्देल, अ.भा. सह–विचार विभाग प्रमुख (पूर्व में मध्य क्षेत्र के संयोजक)
- श्री बलराज सिंह, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संपर्क प्रमुख, केन्द्र काशी (वाराणसी)।
- श्रीमती शीला शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रांत की सह–संयोजिका (पूर्व में अ.भा. सह महिला प्रमुख)
- श्रीमती अलका सैनी, अ.भा. प्रचार टोली सदस्य (पूर्व में अ.भा. सह–महिला प्रमुख थी)
- श्रीमती अर्चना मीना, अभियान की महिला सह समन्वयक तथा मंच की अ.भा. सह–महिला प्रमुख
- श्रीमती विजया रश्मि (मांड्या, कर्नाटक), मंच की अ.भा. सह–महिला प्रमुख
- श्री अजय पत्की (अखिल भारतीय सह–संयोजक) स्वदेशी तीर्थ क्षेत्र, आर्वी वर्धा का काम भी देखेंगे।

स्वदेशी शोध संस्थान

- श्री श्रीधर वेम्बू, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ एडवाइजर
- प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, वाइस चेयरमैन
- डॉ राजीव कुमार, (पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग) – वाइस चेयरमैन
- प्रो. (डॉ) प्रदीप चौहान (जे.एन.यू.दिल्ली), सचिव
- सी.ए. अनिल शर्मा, पालक, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट
- डॉ सर्वजीत कौर (डी.यू. दिल्ली), सह–सचिव
- सी.ए. विजय गोयल, कोष प्रमुख

मीडिया टोली

- सी.ए. गगन
- श्री आलोक सिंह
- श्री अंकित, पूर्णकालिक

उद्यमिता चैम्पियन एवार्ड

- श्री मुकेश शुक्ला
- श्री रवि पोखरना
- श्री साकेत सिंह ठाकुर

अन्य दायित्व

- श्री सतीश चावला, स्वर्णिम भारतवर्ष फाउन्डेशन के प्रमुख के साथ ही पूर्णकालिक कार्य को देखेंगे।
- श्रीमती सुमन मुथा, पूर्णकालिक कार्य सहयोगी रहेंगी।
- श्री वासु योगी, स्वावलंबी भारत अभियान केंद्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के प्रमुख रहेंगे।

दक्षिण क्षेत्र – केरल प्रान्त

- श्री अनिल पिल्लै, केरल प्रान्त संयोजक (पूर्व में प्रान्त संयोजक एवं अभियान के प्रान्त समन्वयक)
- श्री भाग्यनाथ, अभियान के प्रान्त समन्वयक

उत्तर तमिलनाडु

- श्री चंद्र शेखर, पहले से प्रान्त समन्वयक
- कुमारी मैथली, शोध संस्थान की सलाहकार समिति सदस्य के साथ ही प्रान्त महिला प्रमुख।

दक्षिण मध्य क्षेत्र – तेलंगाना

- श्रीमती बाला स्वप्ना (हैदराबाद), प्रांत सह–महिला प्रमुख।

पश्चिम क्षेत्र – कोकण प्रान्त

- श्री किशोर असवानी (मुलुंड, मुम्बई), प्रान्त संयोजक (पहले श्री माधवन नायर, प्रान्त संयोजक थे)

गुजरात प्रान्त

- श्री धवल ठक्कर (लघु उद्योग भारती), अभियान के प्रांत सह–समन्वयक।

मध्य क्षेत्र

- श्री सुधीर दाते, क्षेत्र संयोजक (पूर्व में सह–क्षेत्र संयोजक)

मालवा प्रान्त

- डॉ विशाल पुरोहित, प्रांत सह–संयोजक (पूर्व में इन्दौर महानगर संयोजक)
- श्री राजेश देशमुख, लघु उद्योग भारती (आगर जिला), स्वावलंबी भारत अभियान मालवा प्रांत के सह–समन्वयक।

महाकौशल प्रांत

- प्रो. विकाश सिंह (अमरकंटक विश्वविद्यालय), महाकौशल प्रांत सह–संयोजक (पूर्व में स्व.जा.मं. में शहडोल विभाग संयोजक एवं महाकौशल प्रांत के सम्पर्क प्रमुख)
- श्रीमती दीप्ति पयासी, मध्य प्रदेश की माईएसबीए डिजिटल कार्य प्रमुख (पूर्व में महाकौशल प्रांत सह–संयोजक एवं प्रांत महिला सह–समन्वयक)।

राजस्थान क्षेत्र – चित्तौड़ प्रान्त

- डॉ ज्योति वर्मा, प्रांत महिला कार्य प्रमुख तथा प्रांत सह–संयोजक भी।

- श्री राजेश गौतम, प्रांत सह–संयोजक (पूर्व में बारां विभाग संयोजक)

जोधपुर प्रांत

- श्री अनिल वर्मा, मंच के क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख तथा अभियान के क्षेत्र समन्वयक।
- श्री प्रमोद पालीवाल, प्रांत संयोजक एवं समन्वयक दोनों (पूर्व में मंच के प्रांत सह–संयोजक एवं अभियान के प्रान्त समन्वयक)
- श्री समीर रायजादा, प्रांत सह–संयोजक (पूर्व में प्रांत प्रचार प्रमुख)

जयपुर प्रान्त

- श्री लोकेन्द्र सिंह नरूका, प्रांत सह संयोजक के साथ अभियान के प्रान्त समन्वयक।

उत्तर क्षेत्र – पंजाब प्रांत

- श्री पंकज जिन्दल, केवल प्रांत सह–संयोजक (पूर्व में प्रांत समन्वयक एवं प्रान्त सह–संयोजक)
- श्री सिद्धार्थ शर्मा, अभियान के प्रांत समन्वयक (पूर्व में जालंधर विभाग संयोजक)

दिल्ली

- श्री सत्यवान, सह प्रान्त संयोजक (पूर्व में मंच के सह प्रांत संयोजक एवं अभियान के प्रान्त समन्वयक)
- डॉ सुनीता दहिया, प्रान्त सह–संयोजक (पूर्व में प्रांत महिला प्रमुख)
- श्रीमती अनुराधा बर्थवाल, दिल्ली प्रांत की अभियान प्रांत समन्वयक (पूर्व में मंच की दिल्ली प्रान्त सह महिला प्रमुख)
- डॉ मनजीत सिंह, प्रान्त के सह–संयोजक (पूर्व में विभाग संयोजक)

पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र

- डॉ अमितेश अमित, क्षेत्र संयोजक (पूर्व में क्षेत्र समन्वयक)
- श्री कपिल नारंग, मेरठ प्रांत संयोजक के साथ ही अभियान के क्षेत्र समन्वयक।

मेरठ प्रांत

- श्री प्रशान्त महृषि, मेरठ प्रान्त के सह–संयोजक।

उत्तराखंड प्रान्त

- श्री आशीष रावत, प्रान्त सह–संयोजक।

पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र

- डॉ सर्वेश पाण्डेय, पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनो क्षेत्रों के विचार विभाग प्रमुख।
- श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्र समन्वयक के साथ ही क्षेत्र संयोजक भी।
- डॉ विजय कुमार सिंह, अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य (पूर्व में क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख)

अवध प्रान्त

- श्री वंशीधर मिश्र (बलरामपुर), प्रान्त संयोजक (पूर्व में प्रान्त सह संयोजक)
- श्री रामू स्वदेशी (लखीमपुर–खीरी), प्रान्त सह–संयोजक।

पूर्वी क्षेत्र – उत्तर बंग प्रान्त

- श्री सोमरेश नास्कर, प्रान्त पूर्णकालिक।
- डॉ पालोमी नंदी, प्रान्त महिला कार्य प्रमुख।

मध्य बंग

- श्री विधानचंद्र आकुलि, प्रान्त संगठक।

उड़ीसा पश्चिम

- चंद्रिका लाकरा, प्रान्त महिला कार्य प्रमुख।
- शमिष्ठा देव, प्रान्त सह महिला कार्य प्रमुख।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

- प्रो. दीपक शर्मा (त्रिपुरा), क्षेत्र संयोजक (पूर्व में क्षेत्र सम्पर्क प्रमुख)

मणिपुर

- साबित जी, प्रांत महिला प्रमुख

त्रिपुरा

- श्री सुब्रत नन्दी, प्रांत सह–समन्वयक।

अंत में श्री आर. सुंदरम् ने कन्याकुमारी से नयी उर्जा एवं संकल्प के साथ अपने गन्तव्यों पर कार्य विस्तार करने के आह्वान के साथ सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सत्र का संचालन डॉ राजीव कुमार ने किया।

अंत में कल्याण मंत्र के साथ बैठक संपन्न हुई। ❑❑

नौकरी की जगह स्वरोज़गार पर फोकस करना जरुरीः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि कोरोना के बाद से भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ा है। आज नौकरी की जगह स्वरोज़गार पर फोकस करने की आवश्यकता है। युवाओं का माइंडसेट चैंज करना जरुरी है। शिक्षक, समाज एवं युवाओं के लिए प्रेरक होता है। भारत जैसे देश की बेरोज़गारी की समस्या तभी समाप्त होगी।

श्री कश्मीरी लाल स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एनआईटीटीआर भोपाल में ''युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर एवं रोज़गारोन्मुख भारत प्रशिक्षक के रूप में हमारी भूमिका'' विषय पर आयोजित व्याख्यान माला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर की इंडस्ट्रीज को भारतीय चला रहे हैं। आज स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर, सहकारिता आधारित उद्योंगों आपस में समन्वय कर रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्रम में निटर के निदेशक प्रो. सीसी त्रिपाठी ने कहा कि युवा स्वरोज़गार की तरफ बढ़े, जिससे आत्मनिर्भर भारत की नीव को मजबूती प्रदान हो सके, यह देश की सर्वोच्च प्राथमिकता और चुनौती भी है। कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. अजय सराठे रहे। आभार प्रो पीके पुरोहित एवं कार्यक्रम का संचालन डॉ अंजना तिवारी ने किया। इस व्याख्यान माला में निटर के संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारीगण, प्रशिक्षणार्थी भी उपस्थित रहें।

https://udaipurkiran.in/hindi/today-it-is-important-to-focus-on-self-employment-instead-of-job-kashmiri-lal/

स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े उज्जैन के 75 सदस्य

देश को आर्थिक रूप से सशक्त और विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच की तीन वृहद बैठक कन्याकुमारी में आयोजित की गई। कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र पर संपन्न इस बैठक में देश के 45 प्रांत की 44 मातृ शक्तियों ने हिस्सा लेकर कार्यशाला को ऊर्जावान बनाया।

बैठक में मंच की मध्य भारत सह महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर 10 मिनट का विषय रखा। इसके साथ ही कन्याकुमारी पहुंचे उज्जैन के 75 लोगों से स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान पर चर्चा की। सभी सदस्य मंच की गतिविधियों से प्रेरित हुए और अभियान से जुड़ने को तैयार हुए। ये सभी लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की एक महीने की यात्रा पर थे और इसी दौरान मंच के सदस्यों से भेंट हो गई।

इससे पहले विवेकानंद केंद्र में मध्य भारत सह महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज ने बताया कि कन्याकुमारी में स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा के एक दिन पहले 22 दिसम्बर को हम सभी वहां पहुंच गए थे। वहां एक बस में उज्जैन के आस–पास के जिले के विभिन्न संगठनों और समाजसेवी के करीब 75 भाई–बहन भी वहां मिले। उन्होंने हम सभी को प्रसादी दी। सीमा ने बताया कि, हमने उन्हें अपने संगठन और कन्याकुमारी आने का मकसद बताया।

इसके बाद सभी को अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक आर सुंदरम और सह संयोजक अश्विनी महाजन से मिलवाया। अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख अलका सैनी की उपस्थिति में विवेकानंद केंद्र में भारत माता के स्थान पर तीनों अखिल भारतीय पदाधिकारी ने सीमा भारद्वाज को सही विषय रखने पर आशीर्वाद दिया।

https://www.inhnews.in/news/75-members-of-ujjain-associated-with-swadeshi-jagran-manch

स्वदेशी सामान के इस्तेमाल का रैली से दिया संदेश

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वदेशी जागरण मंच ने जिला मुख्यालय में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। सरवरी से लेकर ढालपुर (हि.प्र.) के प्रदर्शनी मैदान तक निकाली रैली के जरिए लोगों को स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी सामान खरीदने को लेकर प्रेरित किया।

रैली में जब भी बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे, चीन के सामान का बहिष्कार करने के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस दौरान युवाओं को स्वावलंबी बनने को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर सेवा भारती प्रांत छात्रावास प्रमुख राम अयोध्या सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया।

रैली के दौरान बताया गया कि देश में चीन और अन्य विदेशी वस्तुएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि देश में बन रही वस्तुएं नहीं बिक रही हैं। कहा कि युवाओं को स्वरोजगार को लेकर प्रेरित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस मौके नरेंद्र कुमार और हरीश शर्मा, रूपा ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे।

https://www.amarujala.com/himachal-pradesh/kullu/message-given-through-rally-on-use-of-indigenous-goods-kullu-news-c-89-1-ssml1012-14781-2024-01-12

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम पर स्थापित करेगा चेयर पीठ

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के अर्थशास्त्र विभाग में संघ विचारक व अर्थशास्त्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम पर एक प्रेरणा स्त्रोत आसन (चेयर) की स्थापना की जाएगी। इस चेयर का उद्देश्य महान विचारक ठेंगड़ी जी के जीवन कार्यों तथा उनकी शिक्षाओं पर शोध कार्य कर उन्हें नई पीढ़ी से अवगत कराना होगा। ठेंगड़ी से नामित एक शोध निधि (रिसर्च फंड) बनाई जायेगी। उनके जीवन से जुड़ा सम्पूर्ण साहित्य विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगा।

जिससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध कर रहे विद्वानों और भविष्य के उभरते हुए अर्थशास्त्रियों को शोध की नई दिशा मिलेगी। महान अर्थशास्त्री, राष्ट्र ऋषि दतोपंत ठेंगड़ी के राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतन से विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु मार्ग प्रशस्त होगा और यहां के शोधार्थी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसमें अपना भरपूर सहयोग देगा। विश्वविद्यालय के इस कदम से 'विकसित भारत 2047' अभियान में अर्थिक मोर्चे पर युवाओं की भागीदारी को उचित दिशा मिलेगी।

यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि दत्तोपंत ठेंगड़ी महान अर्थशास्त्री, एक दूरदर्शी विद्वान और जनचेतना के शिल्पकार (सृष्टा भी और दृष्टा भी) थे, जिन्होंने कड़े विरोध का सामना करते हुए भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच जैसे जन संगठन बनाए, समकालीन राजनैतिक परिवेश के विरुद्ध काम किया और इसे अपनी अंतर्दृष्टि के अनुसार ढाला।

10 नवंबर, 1920 को महाराष्ट्र के अरवी में जन्मे दत्तोपंत ठेंगड़ी एक प्रमुख आर एस एस प्रचारक थे, जिन्होंने पहले केरल और बाद में बंगाल में काम किया। उन्होंने एकनाथ रानाडे, एच.वी. शेषाद्रि, भाऊराव देवरस, नाना पालकर और नानाजी देशमुख के साथ मिलकर संघ के दर्शन को आकार दिया। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के लिए भी काम किया और 'आदिम जाति संघ' का गठन किया। वे दो कार्यकाल 1964–1976 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर महारत हासिल करने वाले दुर्लभ विद्वानों में से एक दत्तोपंत ठेंगड़ी अनासक्त योग के जीवंत अवतार थे। उन्होंने 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई लोकसंघर्ष समिति की कमान संभाली और 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार होने तक उनके आपातकालीन शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं किया हालाँकि उनकी सलाह पर 'जनसंघ' का 'जनता पार्टी' में विलय कर दिया गया। तदोपरांत उन्होंने पद्मविभूषण की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। वे निष्काम कार्यकर्ता थे।

उनका अवलोकन था कि रूस में साम्यवाद (कम्युनिज्म) रिवर्स गियर में है। स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव व्यापार (डेरिवेटिव ट्रेड), मुद्रा बाजार (करेंसी मार्केट) आदि सट्टा व्यापार जैसी प्रथाओं का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और वेतन रोजगार के मुकाबले स्व–रोजगार को प्राथमिकता दी। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने विभिन्न विषयों पर सौ से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। उनमें से कुछ प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक शीर्षक जैसे 'कार्यकर्ता', ' थर्ड वे', 'क्रांति पर' और 'हिंदू अर्थशास्त्र में प्रस्तावना' आदि बेहद लोकप्रिय हैं।

दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लिखित 'थर्ड वेव' पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि आने वाली पीढ़ी को किसी भी राष्ट्र की सफलता के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की

आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित हिंदू जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता बताई, जिससे बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होगा।

मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक कार्यक्रम, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन आदि दत्तोपंत ठेंगड़ी के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। अपने कार्यों में, ठेंगड़ी जी ने कभी भी निजी निवेश का विरोध नहीं किया, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने घोर पूंजीवाद (क्रॉनी केपिटलिज्म) के साथ–साथ सरकार के व्यवसायों में शामिल होने का भी कड़ा विरोध किया। वे हमेशा कहते से कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। (गर्वनमैंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस)।

संघ परिवार के आर्थिक विश्व–दृष्टिकोण को ठेंगड़ी ने 'तीसरा रास्ता' कहा था, जो पश्चिम के पूंजीवाद के साथ–साथ साम्यवादी आर्थिक सिद्धांतों से अलग था। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कभी भी 'गांव बनाम शहर' दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कभी भी वर्गों के बीच या अमीर और गरीब के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं किया, बल्कि सामूहिक राष्ट्रीय हितों के लिए खड़े रहे। इस प्रकार, उन्होंने 'वर्ग घृणा' और 'वर्ग संघर्ष' पर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी। उन्होंने जीवन के सभी आयामों में 'राष्ट्र हित सर्वोपरि' के विमर्श पर बल दिया और उसे अपने सार्वजनिक जीवन के जीवन दर्शन के रूप स्वीकार किया।

1990 के दशक में, जब देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला किया, तो उन्होंने राष्ट्रवादी आर्थिक दर्शन को लगातार प्रासंगिक बनाए रखने के लिए 'स्वदेशी जागरण मंच' की स्थापना की। 2021 में, केंद्रीय दूरसंचार, आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महान अर्थशास्त्री, राष्ट्रऋषि, विचारक पर एक डाक टिकट जारी किया।

https://www.navodayatimes.in/news/khabre/jambheshwar-university-will-establish-a-chair-in-name-of-rss-thinker-dattopant-thengadi/232429/

युवाओं को स्वावलंबी बना रहा स्वदेशी जागरण मंच

गाजीपुर में पवहारी बाबा आश्रम में 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती युवा दिवस के उपलक्ष्य में तैयारी बैठक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र संपर्क प्रमुख माननीय बलराज जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ पवहारी बाबा केंद्र के संरक्षक श्री अमरनाथ तिवारी जी

प्रान्तीय परिषद के सदस्य श्री नरेंद्र नाथ सिंह जी प्रांत पूर्ण कालिक श्री विवेक कुमार जी प्रांत कार्यालय प्रमुख एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री सुधाकर पांडे जी जिला समन्वयक, स्वावलंबी भारत अभियान श्री कैलाश नाथ तिवारी जी विभाग पूर्णकालिक श्री अमरेंद्र जी जिला पूर्णकाली श्री संकल्प जी जिला संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री विशाल सिंह जी श्री सुधीर जी श्री गोरखनाथ जी ने भागीदारी की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि गाजीपुर जिले के सभी इंटर कॉलेज महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, संदेश यात्रा आदि कार्यक्रमों को विवेकानंद जी के जयंती पर पखवाड़ा के रूप में आयोजित होगा।

https://www.jantakiawaz.org/local/uttar-pradesh/--652427

भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी कार्यक्रमों को बढ़ावा दें: सचिन्द

चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के सुकरीगढ़ा स्थित डॉ. एस. राधाकृष्णन बीएड कालेज में स्वदेशी जागरण मंच ने मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया। इसमें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय मेला प्रमुख श्री सचिन्द्र वरियार, क्षेत्री संयोजक श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, जिला संघ संचालक श्री शत्रुघ्न प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार मेहता आदि शामिल हुए। श्री सचिन्द्र वरियार ने कहा कि स्वदेशी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। रामगढ़ में जिला रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन हो चुका है। स्वदेशी जागरण मंच बेरोजगार युवक, युवतियों को

रोजगार दिलाने के लिए कार्य करेगा। इस दौरान स्वदेशी कार्यक्रम को जिला में विस्तार करने पर बल दिया गया। फरवरी माह में होने वाले स्वदेशी जागरण मंच के मेला को सफल बनाने का निर्णया किया गया।

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत रामगढ़ जिला को स्वावलंबी बनाने का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात सभी लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएड कालेज के सचिव संजय प्रभाकर ने की। मंच संचालन विकास झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अरूण साव और स्वागत भाषण श्री पंचम चौधरी ने दिया। समारोह में कुंटू बाबू, प्रकाश मिश्रा, खिरोधर, आलोक सिंह, वसुध तिवारी, रमेश कुमार वर्मा, अजय चौधरी, दिलीप कुमार वर्मा, प्रो. संजय सिंह, नेपाल महतो, मिथिलेश मंडल, संजीव बरेलिया, बबलू साव, विजय ओझा, रविन्द्र शर्मा, अखिलेश कुमार सिंह, अनिल कुमार महतो, नितेश मोदी आदि महानुभव उपस्थित रहें।

स्वदेशी जागरण मंच ने निकाली "युवा उद्यमिता शोभा यात्रा"

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के शुभ अवसर पर "युवा उद्यमिता शोभा यात्रा" निकाली गई। जिला संयोजक श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में शोभा यात्रा स्वामी विवेकानंद चौक (ट्रैफिक चौक) पर स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रारंभ हुई।

शोभा यात्रा में स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर बिहार प्रांत संयोजक श्री राम शंकर हिन्दवाणी, जिला सह संयोजक श्री निरंजन कुमार, जिला युवा प्रमुख श्री अजीत कुमार चौधरी, जिला मीडिया प्रमुख श्री रवि कुमार, जिला विचार विभाग प्रमुख श्री आलोक कुमार बंटी एवं जिला प्रचार प्रमुख श्री अमरनाथ सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

शोभा यात्रा के बाद गांधी स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए प्रांत संयोजक श्री राम शंकर हिन्दवाणी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र एवं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा युवा उद्यमिता कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। जिला संयोजक श्री विनोद कुमार ने कहा कि भारत को विश्व पटल पर सांस्कृतिक पहचान दिलाने में स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका अद्वितीय, कालजयी रही है।

https://udaipurkiran.in/hindi/swadeshi-jagran-manch-took-out-youth-entrepreneurship-shobha-yatra/

स्वदेशी आंदोलन में शहीद बाबू गेनू जी के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि

नदेसर स्थित स्वदेशी जागरण मंच के काशी प्रान्त कार्यालय में स्वदेशी आंदोलन में प्रथम शहीद बाबू गेनू जी के बलिदान दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। पहले सभी के द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद बाबू गेनू जी के जीवन के बारे में बताया कि कैसे 1908 में महाराष्ट्र के छोटे से गांव में जन्मे एक बालक ने राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर मात्र 22 वर्ष की आयु में अपना बलिदान दे दिया। हमें अपने शहीदों के बलिदानों से यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें इन शहीदों की बलिदानों को समय–समय पर याद करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी शहीदों की महान गाथा पता चले। कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

काशी महानगर के रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ प्रचारक व मंच के अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख बलराज ने किया। कार्यक्रम में प्रान्त संयोजक स्वदेशी जागरण मंच सत्येन्द्र सिंह, पूर्ण कालिक मंच के काशी विभाग अमरेंद्र, पूर्णकालिक स्वदेशी सोनभद्र अजीत, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ उमाकांत, कृषि वैज्ञानिक आनंद प्रकाश, प्रान्त प्रमुख सक्षम विजय, कार्यालय प्रमुख अखिलानन्द, भाजपा कार्यकर्ती निशा, सह संयोजक मंच नवीन, नीरज, अक्षय की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संयोजन मंच की महानगर संयोजिका कविता मालवीय ने किया। ❑❑

https://livevns.news/uttar-pradesh/tribute-paid-to-martyr-babu-genu-ji-on-his-martyrdom-dayphp/cid12988588.htm

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

दिल्ली

बोकारो, झारखंड

मुरादाबाद, उ.प्र.

ओड़िशा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जनवरी 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

अखिल भारतीय वृहद बैठक

कन्याकुमारी (23–25 दिसंबर 2023)

सचित्र झलक

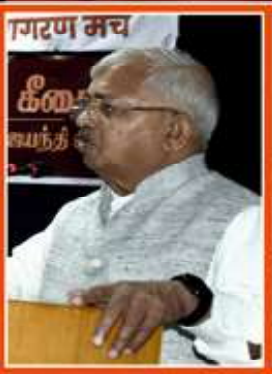

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती